

मिशन क्रियासिद्धि MISSION KRIYASIDDHI

"A Journey Towards Execution"



Presented by
District & Sessions Court, Guna (M.P.)

जिला न्यायालय गुना का इतिहास



भारत की स्वतंत्रता से पहले गुना, ग्वालियर राज्य का एक ज़िला था। गुना जिला न्यायालय, शहर के हनुमान चौक पर एक ऐतिहासिक इमारत में स्थित है, जो सन 1964 के आसपास अपने वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित हुआ था। यह इमारत अपनी "सुंदर संरचना" के लिए प्रसिद्ध है, जिसे विरासत भवन माना जाता है। जिला न्यायालय गुना से वकालत प्रारम्भ करने के उपरांत न्यायमूर्ति श्री आर.सी. लाहोटी ने भारत की न्यायपालिका के सर्वोच्च पद भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद को सुशोभित किया और उनके भाई न्यायमूर्ति श्री के.के. लाहोटी मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदस्थ रहे हैं।

Justice Anil Verma
Judge
High Court of Madhya Pradesh



Judges Cottage "Betwa"
High Court Campus
Gwalior-474011 (M.P.)
Ph. : Off. : 0751-2402205
Resi. : 0751-2402255

Date..... 25-07-2025



संदेश

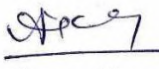
यह अपार हर्ष का विषय है कि जिला एवं सत्र न्यायालय गुना द्वारा एक विशेष अभियान के अंतर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पेरियाममल (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि एवं अन्य बनाम राजामणि एवं अन्य निर्णय दिनांक 6 मार्च 2025 में प्रतिपादित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप अनथक प्रयास कर सराहनीय रूप से निष्पादन प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया गया है और इस अवसर पर उक्त स्मारिका मिशन क्रियासिद्धि का प्रकाशन किया जा रहा है।

वास्तव में डिकी के निष्पादन काफी दुरुह एवं संघर्षपूर्ण कार्य है। प्रीवि काउंसिल ने आज से करीब 150 साल पूर्व जनरल मैनेजर ऑफ द राज दरभंगा बनाम महाराज कुमार रामापूत सिंह (1871-1872) 14 MIA 605:20 ER 912 के मामले में डिकी के निष्पादन में एक टिप्पणी करते हुए यह कहा था कि भारत में एक मुकदमेबाज की मुश्किल तब शुरू होती है, जब उसे एक डिकी प्राप्त हो जाती है। यही बात माननीय उच्चतम न्यायालय ने बाबूलाल बनाम मेसर्स हजारीलाल किशोरीलाल एवं अन्य (1982) SCC 525 के मामले में भी दोहराया थी।

फिर सत्यवती बनाम राजिन्दर सिंह एवं अन्य (2013) 9 SCC 491 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की तीन जजेस की बैंच ने यह टिप्पणी दी थी कि आज तक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। हम दृढ़ता से महसूस करते हैं कि एक डिकी के निष्पादन में अनुचित देरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि डिकी धारक डिकी निष्पादन के माध्यम से अपनी सफलता के फल का आनंद लेने में असमर्थ है तो पक्षकार का सम्पूर्ण प्रयास विफल हो जायेगा।

गुना में पदस्थ न्यायाधीशगणों ने इस मिशन में दीर्घकालीन लंबित निष्पादन प्रकरणों का प्रभावी निराकरण कर पक्षकारों को वास्तविक अर्थों में न्याय प्रदान किया है। इसमें गुना के अधिवक्तागण एवं न्यायालयीन वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के कर्मचारियों के अनुपम सहयोग को भी नकारा नहीं जा सकता है। श्री अमिताभ मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुना के कुशल नेतृत्व में गुना में पदस्थ न्यायाधीशगणों को कड़े परिश्रम, निष्ठा एवं समर्पण भाव से न्यायदान के लिए प्रेरित किया है इस पुनीत कार्य के लिए आप सभी बधाई एवं प्रशंसा के पात्र हैं। मुझे यह विश्वास है कि यह अन्य जिले के न्यायाधीशों के लिए भी प्रेरणादायी एवं मार्गदर्शक दृष्टांत रहेगा और न्याय के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा, जिससे न्यायपालिका के प्रति जनमानस की आस्था भी बढ़ेगी एवं पक्षकारों को सच्चा न्याय मिल सकेगा।

मेरी शुभकामनायें आप सबके साथ हैं।


(जस्टिस अनिल वर्मा)

रथस्यैकं चक्रं भुजगयमिताः सप्ततुरगाः
निरालम्बो मार्गश्चरणविकलो सारथिरपि।
रविर्यात्यन्तं प्रतिदिनमपारस्य नभसः
क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे॥



Everyday Sun travels to the border of endless sky on an unsupported path in a single wheeled chariot carried by seven horses checked by serpents and driven by a feetless charioteer. The action of great people is accomplished by their inner strength and not by instruments.

पदहीन सारथी से चलाया हुआ सर्परज्जुओं से बद्ध सात घोड़ों से जुड़ा एक पहिये का रथ किंतु इसके पश्चात भी सीमित साधन होते हुए भी प्रतिदिन सूर्य निरालंब मार्ग पर अपार आकाश के अंत तक जाता है। अतः यह प्रमाणित है कि महान व्यक्तियों के द्वारा कार्य की सिद्धि साधनों से नहीं अपितु आत्मबल से होती है।

न्याय के फल



धूप में तपे खेत, फसलें उगाने को आतुर, किसान का पसीना, धरती का दुलारा।
मेहनत का फल, निष्पादन का सार, अन्नपूर्णा की कृपा, खुशियों का उपहारा।
नींव से शिखर तक, हर कार्य का निष्पादन, सृजन का उत्सव, जीवन का संपादन।
कर्मयोगी का संकल्प, सफलता का निदान, निष्पादन में ही निहित, मानवता का सम्मान।

एक लक्ष्य : निष्पादन की पूर्णता

हमारे प्रेरणा स्रोत



जस्टिस अनिल वर्मा

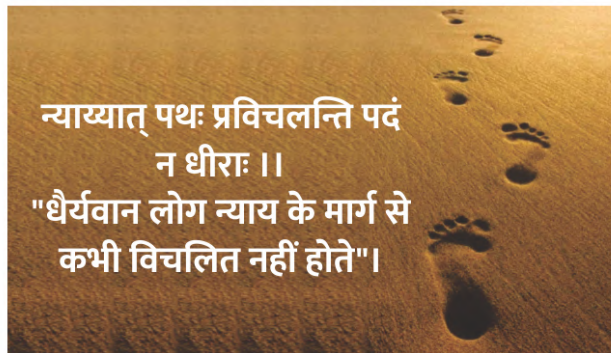
उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश

पोर्टफोलियो जज, गुना

पिछले एक दशक में भारतीय न्यायपालिका को अपने ऐतिहासिक निर्णयों के लिए समूची दुनिया में ख्याति प्राप्त हुई है, परंतु हमारा देश बहुत विशाल है और न्यायालयों एवं न्यायाधीशों की संख्या बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में काफी नगण्य है, इसके अलावा कुछ अन्य कारक और हैं, जो न्यायदान की प्रक्रिया की गति धीमी कर देते हैं, जिससे आज न्यायालयों के लिए आम जनमानस की आस्था प्रभावित हो रही है। यह कहा भी जाता है कि न्याय में देरी, न्याय से इंकार के समान है। दीवानी मामलों में विचारण न्यायालय से निर्णय होने के बाद अपीलों का सिलसिला शुरू होता है, फिर डिक्री के निष्पादन की दुरुह प्रक्रिया आती है, इसमें होने वाला विलम्ब उन डिक्रीधारकों के मन को व्यथित करता है, जिन्होंने मुकदमे के पूरे जीवन चक्र को कठिन परिश्रम एवं जतन से पार किया है। डिक्री मिलने के बावजूद वादी को निष्पादन न्यायालय के समक्ष पहले से जीती हुई लड़ाई फिर से लड़नी पड़ती है। निष्पादन में होने वाले विलम्ब की व्यथा के प्रति न्यायपालिका मूकदर्शक नहीं है और उसने समय-समय पर इसमें होने वाली देरी को दूर करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। इस संबंध में अनेक न्यायदृष्टांतों में मार्गदर्शक सिद्धांत भी प्रतिपादित किए गए हैं। ऐसा ही सार्थक प्रयास माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा राहुल एस. शाह बनाम जितेन्द्र गांधी एवं अन्य के मामले में किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस ऐतिहासिक निर्णय में निष्पादन कार्यवाही के निपटारे में होने वाली देरी से निपटने के लिए अनेक मार्गदर्शक सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि किसी भी मुकदमे में स्पष्ट, असंदिग्ध एवं निष्पादन योग्य डिक्री पारित की जानी चाहिए और निष्पादन न्यायालय को निष्पादन कार्यवाही दाखिल होने की तिथि छह माह के भीतर तत्परतापूर्वक निपटाना चाहिए और अपरिहार्य कारणों से विलम्ब होने पर उन्हें लेखबद्ध करना चाहिए। इसी दिशा में हमारे प्रेरणा स्रोत के मार्गदर्शन में निष्पादन प्रकरणों में त्वरित निराकरण हेतु एक सार्थक प्रयास की पहल

न्याय्यात् पथः प्रविचलन्ति पदं
न धीराः ॥

"धैर्यवान लोग न्याय के मार्ग से
कभी विचलित नहीं होते"।



INDEX

S. No.	Subject	Page Number
1.	Prologue	1
2.	The Team Execution	2-5
3.	Proposal for Mission	6
4.	The Key Objectives	7
5.	Facets of Enforcement : Legal Framework	8-9
6.	Various Modes Of Execution	10-16
7.	Difference Between Section 47& Order 21 Rule 97 CPC	17
8.	Execution Of Money Decree	18-20
9.	Landmark Judgement to address the Problem of Execution	21
10.	Procedure of Transfer of Decree	22-23
11.	Procedure of Execution in Awards Passed under MV Act	24-25
12.	Procedure of Execution in Arbitral Award Passed in Arbitration Proceedings	26-28
13.	Execution of Decree for Specific Performance of Contract	29-31
14.	Execution in a Partition Suit	32-35
15.	Execution Concerning Recovery of Possession of Immovable Property	36
16.	Challenges, Hurdles and Solution	37-45
17.	Table of Landmark Decisions	46
18.	List of Successful Execution of Warrants and Disposal	47-53
19.	Justice in Motion: Tales and Photograph of Triumph	54-82
20.	The Road Forward	83
21.	Conclusion	84

PROLOUGE

"A decree without execution is like a promise without fulfilment — justice must not only be pronounced but delivered."

The execution of decrees is not merely the final stage of litigation; it is the very culmination of justice delivered by the court. Recognizing the urgency and significance of timely execution, the Hon'ble Supreme Court of India, in its landmark judgment "**Periyammal (Dead through LRs) and Ors. vs. V. Rajamani and Anr. Etc (2025 3 SCR 540)**", dated 6th March 2025 issued a vital direction to all trial courts across the country to ensure that the execution process of decrees is completed within six months. This historic pronouncement builds upon the guiding principles laid down in earlier path-setting decisions, notably in ***Rahul S. Shah v. Jinendra Kumar Gandhi*, (2021) 6 SCC 418, and *Bhoj Raj Garg v. Goyal Education and Welfare Society & Ors.*, 2023 1 CivCC 76**. These judgments have consistently emphasized that the efficacy of a decree lies not just in its pronouncement but in its prompt and meaningful execution, reinforcing the faith of litigants in the judicial process.

Taking inspiration from the Hon'ble Supreme Court's decisive stance, the district judiciary of Guna embarks on a mission to revive, reform, and rigorously execute the long-pending civil decrees and awards. This mission is not just a bureaucratic drive — it is an assertion of judicial will, a reaffirmation of the litigants' trust, and a step toward transforming decrees into deliverables. This mission reaffirms that the success of decree execution does not hinge upon the abundance of physical resources or modern equipment, but rather on the **inner determination, judicial willpower, and proactive approach** of the executing court. It is the commitment to justice, not the comfort of logistics, that breathes life into the decree and delivers relief to the decree-holder. With these guiding words in spirit, the **only justifiable and unanimous nomenclature** to this project is:

"THE MISSION "KRIYA SIDDHI" — "FULFILMENT THROUGH DETERMINED ACTION."

Amitabh Mishra

Principal District & Sessions Judge
District Guna (M.P.)

THE TEAM EXECUTION

The Project Coordinator



**Shri Amitabh Mishra
Principal District & Sessions Judge**



**Shri Suresh Kumar Choubey
Chairman,
Consumer Forum Guna**



**Shri Sandeep Kumar
Srivastava
Special Judge
Atrocities**



**Shri Dinesh Prasad Mishra
Principal Judge
Family Court**

The Execution Committee Members



Shri Omprakash Singh
Raghuwanshi
District Judge



Ku. Shailja Gupta
District Judge



Ku. Madhulika Mulley
Chief Judicial Magistrate



Shri Suresh Bargiya
Civil Judge
Junior Division

THE EDITORIAL COMMITTEE MEMBERS

GUNA



Shri Suresh Kumar
Suryawanshi
District Judge



Shri Radhakishan
Malviya
District Judge



Shri Raghvendra
Bhardwaj
District Judge



Smt. Sonali
Sharma
District Judge



Smt. Vandana Tripathi
Civil Judge
Senior Division



Smt. Ritu Shree Gupta
Civil Judge
Senior Division



Shri Dalchand
Civil Judge
Senior Division



Shri Rajkumar Torniya
Civil Judge
Junior Division



Shri Chetan Bajad
Civil Judge
Junior Division



Shri Yash Dubey
Civil Judge
Junior Division



Smt. Shruti Chauhan
Civil Judge
Junior Division



Sushri Ayushi Mittal
Civil Judge
Junior Division

RAGHOGARH



Smt. Prachi Patel
District Judge



Shri Sanjeev Pipladiya
Civil Judge
Senior Division



Shri Ashish Sharma
Civil Judge
Junior Division



Shri Ravi Tanwar
Civil Judge
Junior Division

CHACHODA



Shri Manish Bhatt
District Judge



Sushri Priyam Sen
Civil Judge
Junior Division



Smt. Dimple Kashyap
Civil Judge
Junior Division

AARON



Shri Bude Singh Solanki
Civil Judge
Senior Division

The Satff Members



Shri Balkrishna Sharma
District Nazir, Guna



Shri Virendra Singh Parihar
Deputy Nazir, Guna



Shri Suresh Manjhi
Sale Amin, Guna



Shri Shubham Jha
AG-III, Guna



Anil Sen
Deputy Nazir, Chachoda



Kailash Kushwah
Chachoda



Vinod Sen
Deputy Nazir, Aaron



Amar Batham
Sale Amin, Aaron



Shri Kuldeep Jha
I.T. Assistant, Guna



Pradeep Sharma
Deputy Nazir, Raghogarh



Arjun Jawa
Sale Amin, Raghogarh

The Subordinate Staff Nazarat



Shri Narendra Suman



Shri Ajeet Uppal



Shri Ranveer Raghuwanshi



Shri Mukesh Rajak



Shri Ravi Kori



Shri Sanjeev Jha



Shri Omkar Tiwari



Shri Jagannath Atle



Smt. Seema Chidar

PROPOSAL FOR MISSION “KRIYA SIDDHI”

Background and Genesis of the Mission

In the backdrop of a large pendency of execution proceedings in civil courts, and in view of the landmark judgment of the Hon'ble Supreme Court in *Periyammal (Dead through LRs) & Ors. vs. V. Rajamani & Anr.*, (2025 3 SCR 540), the need for time-bound and effective execution of decrees has been emphatically underscored. The Hon'ble Supreme Court observed that a decree-holder, having obtained a favorable judgment after prolonged litigation, should not suffer further due to undue delay in execution. The Court directed all subordinate courts across the country to prioritize the expeditious disposal of execution petitions and avoid mechanical adjournments.

Taking cognizance of this significant pronouncement and the spirit behind it, **the Portfolio Judge, Guna, Honourable Justice Shri Anil Verma** resolved that these directions of the Apex Court must not remain a formality, but should inspire a structured and mission-mode campaign aimed at clearing the backlog of execution matters in the district. Thus, the execution pendency in the District Court, Guna, was taken up as a **dedicated mission** — now formally titled “**Mission Kriya Siddhi**” — to ensure that execution of decrees is not merely a procedural end, but a substantive delivery of justice.

To achieve the mission's objectives, the **Respected Principal District and Sessions Judge, Guna, Shri Amitabh Mishra** has adopted a structured and mission-oriented strategic approach. This includes systematic identification and prioritization of long-pending execution cases, setting clear disposal timelines at both Taluka and District levels, and holding regular review meetings to monitor progress and address challenges. The strategy also involves proactive judicial intervention to eliminate delays, coordination with administrative and police authorities for effective enforcement, and promotion of compromise through judicial counselling.

Advocates play a vital role in achieving the objectives of the mission. They play a crucial part in resolving technical or procedural delays by proactively engaging with court officials. Due to their positive role and cooperation, the process of justice runs smoothly in the court and the clients get justice without delay. In this direction, the active cooperation provided by the respected members of the District Bar' Association, Guna, is not only unprecedented but will always be remembered.

In addition to this the role of Respected Collector and Superintendent of Police (SP) is crucial in the timely disposal and execution of cases. The Collector ensures administrative coordination, while the SP provides necessary law enforcement support to maintain order and ensure compliance with judicial directives.

“यतो धर्मस्ततो जयः” जहां धर्म है वहां विजय है

THE KEY OBJECTIVES OF MISSION “KRIYA SIDDHI”

The key objectives of Mission “Kriya Siddhi” are as follows:

1. Timely Enforcement of Decrees

To ensure that decrees passed by courts are executed without undue delay, delivering actual relief to decree-holders. The mission recognizes that justice is incomplete without execution and aims to treat it as an essential part of judicial responsibility, not a secondary process.

2. Reduction of Long-Pending Execution Cases

To identify and systematically dispose of stagnant and aged execution matters that have remained unresolved for years. By clearing backlog cases, the mission seeks to improve overall judicial efficiency and reduce the burden on courts.

3. Implementation of Supreme Court Guidelines

To give effect to the directions of the Hon’ble Supreme Court in Periyammal vs. Rajamani, which emphasized the need for prioritizing execution proceedings. The mission is a direct response to this judgment, treating it as a binding mandate rather than a suggestive observation.

4. Structured Monitoring and Judicial Accountability

To implement a framework of regular reviews, disposal targets, and performance tracking under the leadership of the Principal District Judge. This approach aims to maintain discipline, transparency, and consistency in execution work across all courts in the district.

5. Promotion of Alternate Dispute Resolution in Executions

To encourage settlement in executable cases through mediation and compromise, wherever possible. This not only accelerates resolution but also reduces the adversarial burden on courts while ensuring satisfaction for both parties.

"Executio est finis et fructus legis"

An execution is the end and the fruit of the law.

FACETS OF ENFORCEMENT : LEGAL FRAMEWORK

The word “Execution” is not defined anywhere but In simple words execution means enforcement or giving effect to decrees or orders through the process of court. It is the medium through which decree holder compels the judgement debtor to carry out the mandate of the decree or order as the case may be. It enables the decree holder to recover the fruits of the judgement.

The Relevant Provisions on Execution in Code of Civil Procedure 1908 and Civil Rules of Practice are:

1. Sections 36 to 74, Sections 144, 146 & 148 Code of Civil Procedure and Order 21.
2. Chapter XVI Rules 205 to 285 of Civil Rules of Practice.
3. Articles: 125 to 129, 134 to 137 of Limitation Act

Jurisdiction

According to Section 38 of Code of Civil procedure, 1908 - A decree may be executed either by the court which passed it, or by the Court to which it is sent for execution.

According to Section 39 of Code of Civil procedure, 1908 -The Court which passed a decree may, on the application of the decree-holder, send it for execution to another Court of competent jurisdiction.

Different Types Of Execution

- Order XXI Rules 1, 2 & 30 are related to payment under decree.
- Order XXI Rule 31 is related to delivery of specific movable property.
- Order XXI Rule 32 is related to specific performance, restitution of conjugal rights or an injunction.
- Order XXI Rule 34 is related to execution of document or endorsement of negotiable instruments.
- Order XXI Rule 35 & 36 are related to possession of immovable property.

APPLICATION ORDER 21 RULE 11

ORAL APPLICATION : Where a decree is for the payment of money the Court may, on the oral application of the decree-holder at the time of passing of the decree, order immediate execution thereof by the arrest of the judgment-debtor, prior to the preparation of a warrant if he is within the precincts of the Court.

WRITTEN APPLICATION : Decree Holder shall move a written application in the court that originally passed the decree or the court to which it has been transferred for execution. The application shall contain all the essential information viz. suit number, name of parties, date of the decree, any appeal preferred or pending, amount due, name of the person against whom execution is sought, and most importantly the mode in which the assistance of the court is required.

Various modes of execution of decree under CPC

A decree may be carried out in a number of ways, but the Court must adhere to the relevant guidelines outlined in Order 21. **Order XXI Rule 10** states that in order for the decree-holder to have it executed, he must submit an application to the court. **According to Section 51 of the Code**, the various modes of execution of decree under CPC are as follows:

1. By Delivery of any Property specifically decreed
2. By attachment and sale or by sale without attachment of any property
3. By arrest and detention in prison
4. By appointing a receiver
5. In such other manner as the nature of the relief granted may require.

"Executio Juris Non Habet Injuriam"
The execution of the law does no injury.

VARIOUS MODES OF EXECUTION

1. BY DELIVERY OF PROPERTY

MOVABLE PROPERTY: In the event that the property is movable, the decree is carried out by taking possession of it and giving it to the decree-holder or another individual he appoints. The confiscated movable property must be handed to the buyer if it is going to be sold.

IMMOVABLE PROPERTY: Immovable property may be delivered to the individual to whom it has been awarded or to that person's representative when the decree calls for the delivery of such property. Mostly, the decree of sale of immovable property is awarded for enforcing mortgage deed, charge, or for recovery of money or any other kind of encumbrances as deemed fit by the court. The person in whose favor decree is awarded is called the 'Decree Holder', (DHR) and the one incumbent to satisfy it is 'Judgment Debtor' (JDr). Decree of sale comes into being upon adjudication by any court exercising original jurisdiction, and the same can be applied for execution after the prescribed period of appeal, provided it is not preferred by the JDr. Per contra, this can go on until the JDr gives up or exhausts all his legal remedies.

2. ARREST AND DETENTION OF JUDGMENT DEBTOR

Arrest and detention of JDr (Judgment Debtors) in prison for a duration not exceeding the period defined in Section 58, where arrest and detention is permitted under the provision (see Section 51 (c) CPC) is one of the modes of execution of a decree or order. Detaining a person in civil custody, notwithstanding the law's permissiveness, is a court order that violates the individual's human rights. As a result, the judge-made-law has imposed a number of restrictions on the executing Courts' powers when ordering arrest and detention in this mode of execution. Before dealing with the intricate issues of law and procedure in this regard, relevant provisions in the CPC can be referred to once more.

SECTION : 55 CPC

(1) A judgment-debtor may be arrested in execution of a decree at any hour and on any day, and shall, as soon as practicable, be brought before the Court, and his detention may be in the civil prison of the district in which the Court ordering the detention is situate, or, where such civil prison does not afford suitable accommodation, in any other place which the State Government may appoint for the detention of persons ordered by the Courts of such district to be detained:

- Provided, firstly, that, for the purpose of making an arrest under this section, no dwelling-house shall be entered after sunset and before sunrise.
- Provided, secondly, that no outer door of a dwelling-house shall be broken open unless such dwelling-house is in the occupancy of the judgment-debtor and he refuses or in any way prevents access thereto, but when the officer authorised to make the arrest has duly gained access to any dwelling-house, he may break open the door of any room in which he has reason to believe the judgment-debtor is to be found.
- Provided, thirdly, that, if the room is in the actual occupancy of a woman who is not the judgment-debtor and who according to the customs of the country does not appear in public, the officer authorised to make the arrest shall give 15 notice to her that she is at liberty to withdraw, and, after allowing a reasonable time for her to withdraw and giving her reasonable facility for withdrawing, may enter the room for the purpose of making the arrest.

➤ Provided, fourthly, that, where the decree in execution of which a judgment-debtor is arrested, is a decree for the payment of money and the judgment-debtor pays the amount of the decree and the costs of the arrest to the officer arresting him, such officer shall at once release him.

(2) The State Government may, by notification in the Official Gazette, declare that any person or class of persons whose arrest might be attended with danger or inconvenience to the public shall not be liable to arrest in execution of a decree otherwise than in accordance with such procedure as may be prescribed by the State Government in this behalf.

(3) Where a judgment-debtor is arrested in execution of a decree for the payment of money and brought before the Court, the Court shall inform him that he may apply to be declared an insolvent, and that he may be discharged, if he has not committed any act of bad faith regarding the subject of the application and if he complies with provisions of the law of insolvency for the time being in force.

(4) Where a judgment-debtor express his intention to apply to be declared an insolvent and furnishes security, to the satisfaction of the Court, that he will within one month so apply, and that he will appear, when called upon, in any proceeding upon the application or upon the decree in execution of which he was arrested, the Court may release him from arrest, and, if he fails so to apply and to appear, the Court may either direct the security to be realised or commit him to the civil prison in execution of the decree.

PERIOD OF DETENTION [SECTION 58 CPC]

Section 58 determines the duration of detention during which a person can be held, which is determined by the amount of the court's order against him and whether or not he has paid the decreed amount. It states that if the decretal amount exceeds five thousand rupees, an individual cannot be detained for more than three months, and that detention for amounts between two and five thousand rupees cannot exceed six weeks.

No order for detention of the judgment debtor may be made if the total is less than two thousand rupees.

The object of arrest and detention is to provide relief to a decree holder and to send a judgment debtor to civil prison if he fails to pay the decretal sum despite having the financial means to do so. It does, however, protect honest debtors whose failure to pay is due to a fair cause. In order to ensure equal justice, the court must grant debtors the right to be heard.

The clause is a corrective measure. It aims to give the decree-holder a remedy after a suit has been determined in his favour. If the judgment debtor fails to comply with the decree issued against him, such a remedy may be taken in the form of arrest and imprisonment.

The rule extends to someone who is the target of a Code-enforced decree. If a decision is issued in a person's favour, the person must go to court to get the decree carried out. The court will then order the judgment debtor's arrest and imprisonment based on the Code's provisions.

3. ATTACHMENT AND SALE OF PROPERTIES

There are several provisions in the Order 21 CPC, which provide for attachment such as attachment of movables, agricultural produce, debt, shares, attachment of salary of Govt.employees, attachment of salary of private employees, attachment of partition property, negotiable instruments, property in the custody of court, attachment of decree and attachment of immovable properties etc. The different provisions provide for different modes of execution and provide specific manner of attachment and the

consequences for the breach of an order of attachment and the fastening of liability. We are going to see the same in the present discussion.

Attachment is provided in the Civil Procedure Code, 1908 at Two Stages:

- (i) One is stage before passing of Judgment which is provided under Order-38 of CPC from Rules 5 to 13;
- (ii) Second is after passing of decree by way of attachment of movables, attachment of Salary Attachment of a decree attachment of Negotiable Instruments, attachment of Immovables. The contours of attachment and sale in Execution of decrees is provided under Section -60 of CPC.

Section - 39(1)(b) says: that if the Judgment Debtor has no property within the local limits of the jurisdiction of the Court which passed the decree, the decree may be transferred to such Court within the local limits of whose jurisdiction the Judgment Debtor has property.

Section - 39(4) says: that nothing in Sec.39 shall be deemed to authorize the court which passed a decree to execute such a decree against any person or property outside the local limits of its jurisdiction. A decree may also be transferred to the court in another State.

What can be Attached ?

In Execution Proceedings provided for attachment of the property of the Judgment debtor is provided under different Rules. It also provides for the manner of the attachment of movables and agricultural property and custody of the movables and agricultural property.

The following items can be attached:

- 1) Movables (Rule 43 and 43-A)
- 2) Agricultural produce (Rule 44 and 45)
- 3) Debt, Shares and movable property not in the possession of the Judgment debtor (Rule 46).
- 4) Attachment of share in the movables (Rule 47)
- 5) Attachment of Salary of Govt. Employees, Railway Company or Local Authority (Rule 48).
- 6) Attachment of salary or allowances of private employees (Rule 48A)
- 7) Attachment of partnership property – (Rule 41)
- 8) Attachment of Negotiable Instruments (Rule 51)
- 9) Attachment of property in the custody of Court or Public Officer (R.52)
- 10) Attachment of Decree (Rule 53)
- 11) Attachment of Immovable property (Rule 54)

PROCLAMATION OF ATTACHMENT

It is important to note how the order of attachment shall be proclaimed. The order shall be proclaimed adjacent to the property sought to be attached by beat of Drum, or other customary mode. A copy of the order of attachment shall be affixed at the following places:

- on conspicuous part of the property
- in the Court house
- if revenue is payable to the Government from such property, the District Collector's office and in the Tahsildar office
- If the property is a land situated in a village in the Gram panchayat office.

- By an amendment made in Madras Sub Rule (2) of R.54 is amended. It requires that if the property is situated within the cantonment limits the order of attachment shall be affixed in the office of the local cantonment Board and the Military Assets Officers concerned.
- if the property is situated within the limits of Municipality, the order of attachment shall be affixed in the office of the Municipality within the limits of which the property is situated.

OBJECTIONS TO ATTACHMENT [ORDER 21 RULE 58 CPC]

- (1) Where any claim is preferred to, or any objection is made to the attachment of, any property attached in execution of a decree on the ground that such property is not liable to such attachment, the Court shall proceed to adjudicate upon the claim or objection in accordance with the provisions herein contained:

Provided that no such claim or objection shall be entertained—

- (a) where, before the claim is preferred or objection is made, the property attached has already been sold; or
 - (b) where the Court considers that the claim or objection was designedly or unnecessarily delayed.
- (2) All questions (including questions relating to right, title or interest in the property attached) arising between the parties to a proceeding or their representatives under this rule and relevant to the adjudication of the claim or objection, shall be determined by the Court dealing with the claim or objection and not by a separate suit.

PREPARING NOTICE OF SALE & ITS PROCLAMATION

The executing court is empowered to attach property, and publicly auction it to pay the person entitled proceeds of the sale in satisfaction of the decretal amount.

In this regards, the court shall issue a notice to both DHr and JDr to present themselves in court on the day and date fixed for drawing proclamation of sale notice. It is prepared in the language of the court and contains all the essentials viz. time and place of sale, specifications and description of property to be sold, revenue assessed if any due, any encumbrance to which the property is liable, decreed amount, estimate value of the property as ascertained by the court, judgment debtor and decree-holder or any other material information necessary that shall aid the purchaser in its evaluation.

Care is taken to sell only that part of the property that is necessary to satisfy the decree.

The court is also empowered to summon anyone, or demand documents deemed necessary in preparation of this proclamation notice. Henceforth, the court shall order the Nazir of the Court for causing service of this drawn proclamation of sale. The same shall be published and announced by beat of drums. A copy of the same is affixed on a conspicuous part of the property and the courthouse. After performing all such acts, Nazir shall prepare a report for the information of the executing court.

- In case the property to be sold is other than agricultural land, than the court also gives the notice to the Registrar to inspect the property and gives its estimated market value to the court. The court also gives notice to the decree holder for giving the market value of the attached property.

WARRANT OF SALE

The court shall issue a warrant of sale order in the name of the bailiff to publicly auction as per the details mentioned in the warrant on the date and place specified and report back to court with an endorsement certifying the manner in which sale has been executed or the reason why it has not been executed.

ADJOURNMENT, POSTPONMENT OR STOPPAGE OF SALE

- The court may at its discretion adjourn sale to a specified date and hour, and so can an officer conducting the sale but after recording reasons thereto. And if the auction is taking place within the precincts of the courthouse then only after leave of court.
- Sale can be adjourned when the bid amount is not adequate.
- Sale can be adjourned if the purchaser fails to pay 25% of the bid amount immediately on closing of bid, and postponed if he does not pay the remaining sum within 15 days of the successful bid.
- Provided, if the JDr is able to satisfy the court that if the given time he shall be able to raise the decreed amount either by way of leasing, mortgaging or selling the property in question or other property the court may postpone the sale on such terms and for such period as it deems fit. The court shall grant a certificate to the JDr in this respect. All monies raised by JDr shall be paid to the Dhr.
- If for any reason purchaser defaults on paying the full bid amount then after defraying the expenses involved in the auction, the remainder sum may be forfeited in the favor of the government, if the court so decides. And the property shall be resold after issuing a fresh proclamation.
- The sale could be stopped any time before the lot is knocked down if the Judgement debtor tenders to the officer conducting the sale the full decreed amount along with costs and expenses or on producing proof of its deposit in execution court.
- Sale can stay pending adjudication of any claim or objection even if it is received after proclamation of attachment and advertisement for sale. Or conditionally allowed pending adjudication that if property is sold the same shall not be confirmed or pass orders subject to such terms and conditions as to security etc.

Note: If adjournment exceeds 30 days then fresh proclamation is to be issued, published and affixed as mentioned earlier.

APPLICATION TO SET ASIDE SALE [ORDER 21 RULE 89 CPC]

- Any person claiming an interest in the property sold may apply to the court to set it aside subject to payment in court 5% of purchase money and sum equal to that specified in proclamation notice i.e. decreed amount.
- Decree holder, purchaser or any other person having interest in the distribution of proceeds from the sale may apply for setting aside the sale on grounds of fraud or material irregularity in publishing or conducting the auction, provided injury sustained is substantial. No such application shall be accepted if the applicant had an opportunity to approach the court on an earlier occasion but has failed to do so.

- Purchaser may apply to set aside the sale on the ground that the JDr has no saleable interest in the decreed property.

Pertaining to all of the above cases, notice is issued to the other party to show cause before adjudication.

SUCCESSFUL SALE [ORDER 21 RULE 84 & 85 CPC]

If a sale is successful, then the purchaser is required to immediately deposit 25% of the sale amount and the rest within 15 days of successful bid unless Decree holder is the purchaser himself with the prior permission of the court.

DISTRIBUTION OF MONEY REALISED FROM SALE [ORDER 21 RULE 93 CPC]

After defraying expenses involved in the sale of property, pay to decree-holder his full entitlement, and if any balance remains that shall be given to the Judgement debtor. If on the contrary money realized from sale is not sufficient to satisfy the decreed amount then the decree holder can apply to the court for recovery of balance amount provided it is legally recoverable.

CERTIFICATE TO PURCHASER [ORDER 21 RULE 94 CPC]

Once the sale has become absolute, and there is no litigation pending in either of the courts i.e. executing court or courts of appeal the court shall issue a certificate in favor of the purchaser containing the details of the property and the day and date he is declared to be the absolute owner of the immovable property. If the property in question is occupied by a tenant the court shall issue a proclamation bringing to his notice the name of the new owner.

Finally, if for any reason the purchaser is being obstructed from gaining possession the court shall intervene on the application, and order the bailiff to put the purchaser in possession of the sold property.

4. APPOINTMENT OF RECEIVERS IN EXECUTION

The power to appoint receivers in execution should be more freely used for the purpose of realizing the money decreed where the property is sufficiently large to bear the extra cost of appointment of a receiver.

- A Court, ordering attachment of land assessed to the payment of revenue to the Government, should send two copies of the order to the Collector with a request to have one of them affixed to the notice board in his office. As the other copy is required for the Record of Rights, one copy only need be sent, if the land is in a village where the Record of Rights has not been introduced. District Judges should obtain lists of such villages for their Courts and subordinate Courts, from the Collector.
- Similarly, a Court by whose order attachment is removed or ceases should send intimation to the Collector in standard Form No. Civ. A-234.
- The Collector should certify the affixing to or the removal from, his notice-board of orders of attachment.

QUESTIONS TO BE DETERMINED BY EXECUTING COURT

The relevant provisions under Code of Civil Procedure, 1908 which are meant to tackle objections to the execution are primarily Section 47, O. 21 R. 97 and O. 21 R. 99 CPC.

SECTION - 47 CPC : Exclusive jurisdiction has been conferred on the executing court in respect of all matters relating to the execution, discharge, or satisfaction of a decree arising between the parties or their representatives. Once the suit is decreed, this section requires that the executing court alone should determine all questions in execution proceedings, and filing of a separate suit is barred. This Section provides for a situation when the dispute is between parties to the suit and does not cater to dispute between decree holder and stranger to the suit proceedings.

ORDER 21 RULE 97 CPC : The next provision is ORDER 21 RULE 97 CPC which is reproduced as under -

- Where the holder of a decree for the possession of immovable property or the purchaser of any such property sold in execution of a decree is resisted or obstructed by any person in obtaining possession of the property, he may make an application to the Court complaining of such resistance or obstruction.
- Where any application is made under sub-rule (1), the Court shall proceed to adjudicate upon the application in accordance with the provisions herein contained.

"Fraus et jus nunquam cohabitant"
fraud and justice never dwell together

DIFFERENCE BETWEEN SECTION 47 AND ORDER 21 RULE 97 CPC

Difference between Section 47 and Order 21 and Rule 97 CPC is that whereas Section 47 deals with execution of all kinds of decree, O. 21 R. 97 only deals with the execution of the decree for possession of immovable property.

Second difference is that whereas Section 47 only pertains to resolution of disputes arising between the parties to the suit, O.21 R.97 CPC envisages “any person” which includes stranger to the suit proceedings.

The question whether the word “any person” also includes a person other than judgment debtor i.e. stranger to the suit proceedings, first came up before the Apex Court in the celebrated case of **Brahmdev Choudhary v. Rishikesh Prasad Jaiswal and another, (1997) 3 SCC 694**. In this case, it was argued that a stranger to suit proceedings has no *locus standi* prior to execution of decree in view of O. 21 R. 99 which categorically provides for remedy to such person when he is dispossessed of immovable property.

NEED FOR ADJUDICATION :

O. 21 R. 97 (2) provides that when any application is filed under sub-rule (1), the Court shall proceed to adjudicate upon the application and in accordance with the provisions herein contained. The word “adjudication” replaces the word “investigation” by the amendment of 1976. This substitution now gives immense powers to the Court in deciding the rights, title or interest in the property of the object.

Adjudication need not necessarily involves a detailed enquiry or collection of evidence. Court can make adjudication on admitted facts or even on the averments made by resistor. Of course the Court can direct the parties to adduce evidence for such determination as the Court deems necessary. This has been so held in the case of *Silver Line Forum Pvt. Ltd. v. Rajiv Trust*, AIR 1998 SC 1754.

PROVIDING POLICE HELP AGAINST THE OBSTRUCTOR

Many a times it is seen that when a decree holder is obstructed in the execution of the decree, the decree holder files an application for providing police help by making an application under O. 21 R. 35 CPC and the Executing Court also goes on to allow the application for police help after recording the statements of *Machkuri*. The question is whether such type of an order is proper or not. The Apex Court was confronted with the same question in *Brahmdev Choudhary's case* (supra).

It was held that when the resistance is offered by the purported stranger to a decree and which comes to be noted by the Executing Court as well as by the decree holder, the remedy available to the decree holder is only under O. 21 R. 97 (1) CPC and he cannot bypass such obstruction and insist on re-issuance of warrant for possession under O. 21 R. 35 with the help of police force as that would amount to bypassing and circumventing the procedure laid down under O. 21 R. 97 in connection with removal of obstruction to purported strangers to the decree.

It was observed by the Apex Court that when the decree holder is obstructed by the stranger to the decree from possession of immovable property, the stranger cannot be forcibly evicted with police help under O. 21 R. 35 CPC. Application of the decree holder for police help under O. 21 R. 35 CPC would in fact be deemed as an application under O.21 R. 97 CPC and the Court will be required to adjudicate the matter. It is only after such adjudication that the Court may provide police help if such a stranger still refuses to vacate the premises.

“Ignorantia Juris Non Excusat” ignorance of the law is no excuse

EXECUTION OF MONEY DECREE

ORDER 21 RULE 30 OF THE CODE : Every decree for the payment of money, including a decree for the payment of money as the alternative to some other relief, may be executed by the **detention in the civil prison** of the judgment-debtor, or by the **attachment and sale of his property**, or **by both**.

- Order XXI Rule 1(b) of the CPC enables the judgment-debtor to directly pay the decretal amount to the decree-holder
- Order XXI Rule 1(a) of the CPC gives an option to the judgment-debtor to deposit the decretal/award amount with the Executing Court and give the notice of deposit to the decree-holder under Order XXI Rule 1(2) of the CPC (Like MACT)
- If the decree-holder is aware of the assets of the judgment-debtor, the Executing Court attaches the assets at the very threshold of the execution proceedings.
- The Executing Court thereafter initiates proceedings for sale of the attached assets of the judgment-debtor to satisfy the decree.
- Section 58 and 59 of the Code provides for the time period for the detention and release of Judgement Debtor in case on execution of money decree.

PROHIBITION OF ARREST AND DETENTION IN CIVIL PRISON [Section 56 CPC]:

The Court shall not order the arrest or detention in the civil prison of a woman in execution of a decree for the payment of money.

NOTICE TO JUDGEMENT DEBTOR

Where the decree is for the payment of money and the application is made for the arrest and detention of the judgment-debtor, the Court shall instead of issuing a warrant for arrest, issue a notice calling upon the judgment-debtor to appear and show cause why he should not be committed to civil prison in execution of the decree.

The purpose of issuing notice is to afford protection to the honest debtors incapable of paying dues for reasons beyond their control. The provision for issuing notice and allowing the judgment-debtor to show cause recognizes a rule of natural justice that no person should be condemned unheard.

- ***It is important to note that where the decree is for the payment of money, execution by detention in prison shall not be ordered unless there is anyone of the three conditions mentioned under proviso of section 51 of the code and under Order 21 Rule 37 and 40 the court after giving the judgment-debtor an opportunity of showing cause why he should not be committed to prison.***
- ***According to Order 21 Rule 11(A) where an application is made for the arrest and detention in prison of the judgment-debtor, it shall state, or be accompanied by an affidavit stating, the grounds on which arrest is applied for.***

In **Subhash Chand Jain vs Central Bank Of India, AIR1999 MP 195** the Madhya Pradesh High Court held that:

“7.....it is evident that when executing Court exercises discretion of issuing show cause against the detention in prison then executing Court has to follow the procedure laid down in Clause (1) of Rule 40 of Order 21 which provides that after notice issued under Rule 37; the Court shall proceed to hear the decree holder and to take all such evidence as may be produced by him in support of his application for execution and shall then give the judgment-debtor an opportunity of showing cause why he should not be committed to the civil prison. In the case in hand the executing Court after issuing show cause did not hold any enquiry as contemplated of Clause (1) of Rule 40 of Order 21 nor has complied the conditions laid down in proviso to Section 51 so as to record its reasons after its satisfaction for detaining or sending the judgment-debtor in civil prison. **Therefore, the order passed without following the mandatory provisions cannot be sustained and is quashed.**”

LEGAL REPRESENTATIVES OF DECREE HOLDER

In the case of **Tarabai Jain And Ors. vs Shivnarayan Kothari, 1997(2)MPLJ287** the Madhya Pradesh High Court has held that:

“If the decree-holder died during pendency of execution or before execution is filed and the applicants applied before the Court for substitution of their names as legal representatives of the deceased decree-holder. The Court has held that the legal representatives cannot proceed with execution unless they produce succession certificate.....”

LEGAL REPRESENTATIVES OF JUDGEMENT DEBTOR

Where the decree is executed against the legal representative of judgement debtor, he shall be liable only to the extent of the property of the deceased which has come to his hands and has not been duly disposed of. **It is important to note that the execution of decree can't be ordered by detention in civil prison of the legal representatives.**

CONTEMPT PROCEEDINGS AGAINST GOVERNMENT OFFICERS

- No contempt proceedings can be initiated against the government officers for non compliance of execution of money decree passed against the State unless the court comes to the conclusion that such non compliance is done wilfully by the concerned officer.
- In the case of **Horilal Vs Bhajanlal ILR 2009 MP 3061** the Hon'ble Madhya Pradesh High Court held that:

“.....When the code of civil procedure provides for instituting a proceeding for execution of judgement and decree, than the contempt application under Article 215 read with Section 12 of Contempts of Court Act is not maintainable as statute provides for a mechanism for execution of the decree passed.”

THE CHALLENGES OF EXECUTING MONEY DECREES IN INDIA

It is a well-known adage in legal circles that obtaining a money decree from an Indian court is often easier than actually executing it and recovering the awarded sum from the Judgment Debtor (hereinafter referred to as the JDr). The JDr can ultimately prevail by failing to pay the decreed amount, leaving the Decree Holder (hereinafter referred to as the DHr) unable to recover the money they are legally entitled to.

In a significant number of cases, even after successfully obtaining a money decree, the DHr faces substantial challenges in the execution proceedings, resulting in the decree remaining largely on paper. The process of executing a decree is often prolonged, expensive, and exhausting, leading many DHs to abandon their efforts out of frustration. Execution of a money decree is an arduous task, requiring great effort and perseverance on the part of the DHr to recover the sum they are entitled to as per the court's judgment.

The executing court, upon receiving a report of non-satisfaction of the decree, issues warrants for attachment of the JDr's movable properties. A court-appointed bailiff then visits the JDr's premises to attach the movable assets as per the list provided by the DHr, if they are found at the given address. **If the DHr manages to obtain the JDr's bank account details, the executing court may issue warrants for attachment of the balance funds in the account.**

IF JUDGEMENT DEBTOR MOVES OUTSIDE THE JURISDICTION :

When the JDr is an individual, they may relocate to a different place after the decree is passed, making it challenging for the DHr to trace their whereabouts. Even if some movable assets are found at the JDr's premises, they are often of little value, being mostly household items. If the JDr moves outside the jurisdiction of the executing court or to another state, the DHr faces even greater difficulty in recovering the money, as the decree must then be transferred to the court having jurisdiction over the Jdr's new place of residence or business.

SALARIED PERSON AS JUDGEMENT DEBTOR

In cases where the JDr is a salaried employee, the executing court can attach a maximum of one-third of their salary for a period of up to 2 years under Order 21 Rule 48 read with Section 60 CPC.

RECOVERY BY ATTACHMENT OF IMMOVABLE PROPERTY

If the DHr is unable to recover the decreed amount by attaching the Jdr's movable properties, they may seek attachment of the JDr's immovable property under Order 21 Rule 54 CPC. **However, if the JDr only owns a single dwelling house, it cannot be attached in execution of a money decree.**

Even if the JDr owns multiple properties, if they are in the name of their parents, spouse, or children, who are not parties to the decree, these properties cannot be attached or sold to satisfy the decree.

Moreover, if the JDr's immovable property is mortgaged to a bank, which has a secured charge over the property, the DH will be unable to sell the property to recover the money, as the bank's claim will take precedence.

" A Decree Holder should not be driven to the long and expensive process of execution which makes the judgment a paper decree" - Justice V.R. Krishna Iyer

LAND MARK JUDGEMENT TO ADDRESS THE PROBLEM OF EXECUTION

To address the challenges regarding the execution of decrees, the Honourable Justice S. Ravindra Bhat, Justice L. Nageswara Rao, and Justice S.A. Bobde, Supreme Court of India, in the landmark Judgment dated 22.04.2021 in **Rahul S Shah v. Jitendra Kumar : (2021) SCR (4) 279** has mandated courts to exercise their powers under Order 21 Rule 11 CPC to ensure immediate execution of money decrees upon an oral application. The Court has also directed that before the settlement of issues in a suit for payment of money, the defendant may be required to disclose their assets on oath to the extent of their liability. Furthermore, courts may, at any stage during the suit's pendency, demand security from the defendant to ensure the satisfaction of any decree that may be passed.

To effectively execute money decrees, trial courts must exercise their powers in terms of the Supreme Court's ruling in **Rahul S Shah v. Jitendra Kumar** and compel defendants to disclose their assets or furnish security for the suit amount, especially when the defendant's case appears weak and a decree is likely to be passed against them.

During the trial of a money suit, courts should carefully examine the defendant's defence and assess the likelihood of success, similar to their approach in summary suits filed under Order 37 CPC. If the court finds the defendant's defence to be weak, it should direct the defendant to provide security for the suit amount, disclose their assets, and restrain them from disposing of those assets during the pendency of the suit. The trial court must protect the plaintiff's interests and, at the time of passing the decree, secure the defendant's presence and immediately initiate execution proceedings upon an oral application to ensure the decree's satisfaction.

In the case of **Pratibha Singh Vs. Shanti Devi (2003) 2 SCC 330**, While discussing the scope of the Section 47 of the Code of the Civil Procedure, Hon'ble Supreme Court, held that when the suit as to immovable property has been decreed and the property is not definitely identified, the defect in the court record caused by overlooking of provisions contained in Order VII Rule 3, in Order XX Rule 3 is capable of being cured. After, all a successful plaintiff should not be deprived of the fruits of the decree. Resort can be had to Section 152 or Section 47 of the Code of Civil Procedure depending on the facts and circumstances of each case which of two provision be more appropriate, just and convenient to invoke. Being an inadvertent error not effecting the merit of the case, it may be corrected under Section 152 CPC by the court which passed the decree by supplying the omission. Alternatively, the exact description of decretal property may be ascertained, by the executing court as a question relating to execution, discharge or satisfaction of the decree within the meaning of this Section. A decree of a competent court should not be allow to defeated on account of an accidental slip or omission, we think it would be more appropriate to invoke Section 47 CPC.

**"Ex injuria jus non oritur"
law does not arise from injustice**

PROCEDURE OF TRANSFER OF DECREE

डिक्री के अंतरण की प्रक्रिया

सामान्यतः किसी भी डिक्री का निष्पादन डिक्री पारित करने वाले न्यायालय द्वारा किया जाता है, लेकिन डिक्रीधारी की सुविधा एवं अन्य कारकों को दृष्टिगत रखते हुए डिक्री के सफलतापूर्वक निष्पादन हेतु डिक्री अन्य न्यायालय को अंतरित भी की जा सकती है।

- **सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 38** यह उपबंध करती है कि डिक्री या तो उसके पारित करने वाले न्यायालय द्वारा या उस न्यायालय द्वारा, जिसे वह निष्पादन के लिए भेजी गई है, निष्पादित की जा सकेगी।
- मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा पारित अधिनिर्णय के अनुक्रम में अधिनिर्णीत राशि की बसूली हेतु प्रस्तुत होने वाले प्रवर्तन प्रकरणों में सामान्यतः यह देखने में आता है कि जहां बीमा कंपनी के विरुद्ध अधिनिर्णय नहीं है और वाहन स्वामी एवं चालक के विरुद्ध ही अधिनिर्णय पारित किया गया है, वहां वाहन स्वामी एवं चालक अधिनिर्णय पारित करने वाले अधिकरण के क्षेत्राधिकार में निवास नहीं करते हैं और उनकी ऐसी कोई संपत्ति, जिससे अधिनिर्णय राशि की बसूली की जा सके, अधिकरण के क्षेत्राधिकार में नहीं होती और तब अधिनिर्णय पारित करने वाले अधिकरण द्वारा राशि बसूल की जाना संभव नहीं हो पाता।
- ऐसी स्थिति में जबकि अधिनिर्णय पारित करने वाले अधिकरण के क्षेत्राधिकार में निर्णीतऋणी न तो निवास करता और न ही कोई कारोबार करता है और न उसकी संपत्ति स्थित है, तब **सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 39** से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाना चाहिए, यह धारा 39 इस प्रकार है –

डिक्री का अंतरण

- (1) डिक्री पारित करने वाला न्यायालय डिक्रीदार के आवेदन पर उसे [सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय] अन्य न्यायालय को निष्पादन के लिए भेजेगा।
 - (क) यदि वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध डिक्री पारित की गई है, ऐसे अन्य न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है या कारोबार करता है, अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है, अथवा
 - (ख) यदि ऐसे व्यक्ति की संपत्ति, जो ऐसी डिक्री की तुष्टि के लिए पर्याप्त हो, डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर नहीं है और ऐसे अन्य न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर है, अथवा,
 - (ग) यदि डिक्री उसे पारित करने वाले न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर स्थित स्थावर संपत्ति के विक्रय या परिदान का निवेश देती है, अथवा,
 - (घ) यदि डिक्री पारित करने वाला न्यायालय किसी अन्य कारण से जिसे वह लेखबद्ध करेगा, यह विचार करता है कि डिक्री का निष्पादन ऐसे अन्य न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।
- (2) डिक्री पारित करने वाला न्यायालय स्वप्रेरणा से उसे सक्षम अधिकारिता वाले किसी भी अधीनस्थ न्यायालय को निष्पादन के लिए भेज सकेगा।
- (3) इस धारा के प्रयोजन के लिए, किसी न्यायालय को सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय समझा जाएगा, यदि उस न्यायालय को डिक्री के अंतरण के लिए आवेदन करने के समय, ऐसे न्यायालय को उस वाद का विचारण करने की अधिकारिता होती जिसमें ऐसे डिक्री पारित की गई थी।

- **धारा 39 सी.पी.सी. की उपधारा 4 के अनुसार धारा 39** की कोई भी बात उस न्यायालय को, जिसने डिक्री पारित की, उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर किसी व्यक्ति अथवा संपत्ति के विरुद्ध निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत करने वाली नहीं समझी जाएगी अर्थात् डिक्री पारित करने वाला न्यायालय, डिक्री का निष्पादन अपनी अधिकारिता के अंतर्गत ही कर सकता है और तब ऐसी स्थिति में आवश्यक हो जाता है कि धारा 39 में जिस प्रकार की डिक्री के निष्पादन को बताया गया है, उस प्रकृति की डिक्री और उसके निष्पादन की स्थिति में डिक्री को ऐसे न्यायालय को अंतरित किया जाए, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत निर्णीतऋणी निवास करता है या कारोबार करता है, अभिलाभ के लिए काम करता है अथवा उसकी ऐसी संपत्ति, जो डिक्री की तुष्टि के लिए पर्याप्त हो, उस न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमा में है।

प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि डिक्री का अंतरण क्या डिक्री पारित करने वाले न्यायालय द्वारा स्वयं के विवेक से किया जा सकता है ?

- इस संबंध में यदि धारा 39 सी.पी.सी. को देखें, तो उपधारा 1 डिक्रीदार के आवेदन पर डिक्री को अंतरित करने के संबंध में उपबंध करती है, लेकिन जब डिक्री पारित करने वाले न्यायालय के क्षेत्राधिकार में न तो निर्णीतऋणी निवास करता है और न ही कारोबार करता है और न ही उसकी ऐसी कोई संपत्ति स्थित है, जिससे डिक्री की संपत्ति हो सके और उपधारा 4 अधिकारिता के बाहर डिक्री के निष्पादन को वर्जित करती है, तब यदि डिक्रीदार आवेदन न करे, तो एक कठिन परिस्थिति उत्पन्न होगी, जिसमें न्यायालय न तो डिक्री का अंतरण कर सकेगा और न ही निष्पादन, तब **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत मोहनलाल गोयनका विरुद्ध विनोय कृष्णा मुखर्जी व अन्य ए.आई.आर. 1953 एस.सी. 65** अवलोकनीय है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया है कि डिक्री पारित करने वाला न्यायालय स्वयं के विवेक से भी डिक्री का अंतरण ऐसे न्यायालय को कर सकता है, जिसके द्वारा डिक्री का वास्तविक निष्पादन किया जाना संभव हो।
- इस प्रकार मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा पारित अधिनिर्णय के अनुक्रम में भी जहां वाहन स्वामी या चालक अधिकरण के क्षेत्राधिकार में निवास या कारोबार, अभिलाभ के लिए काम नहीं करते हैं और उनकी ऐसी कोई संपत्ति भी स्थित नहीं है, जिससे डिक्रीधन की तुष्टि की जा सके, वहां अधिकरण द्वारा डिक्रीदार के आवेदन पर अथवा स्वविवेक से डिक्री का अंतरण क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय को करना चाहिए।
- अंतरण के समय जिन बातों का ध्यान रखना है, उनके संबंध में मार्गदर्शन **आदेश 21 नियम 6 सी.पी.सी.** से प्राप्त किया जा सकता है, जो इस प्रकार है –

जहां न्यायालय यह चाहता है कि उसकी अपनी डिक्री किसी अन्य न्यायालय द्वारा निष्पादित की जाए, वहां प्रक्रिया – डिक्री को निष्पादन के लिए भेजने वाला न्यायालय निम्नलिखित को भेजेगा अर्थात् –

- (क) डिक्री की प्रति,
- (ख) यह उपवर्णित करने वाला प्रमाण पत्र कि डिक्री की तुष्टि उस न्यायालय की अधिकारिता के भीतर जिसने उसे पारित किया था। निष्पादन द्वारा अभिप्राप्त नहीं की गई है या जहां डिक्री का निष्पादन भागतः हुआ है, वहां वह विस्तार जिस तक तुष्टि अभिप्राप्त कर ली गई है और डिक्री का जो भाग अतुष्ट रहा है, वह भाग उपवर्णित करने वाला प्रमाण पत्र; तथा
- (ग) डिक्री के निष्पादन के किसी आदेश की प्रति या ऐसा कोई भी आदेश नहीं किया गया है तो उस भाव का प्रमाण पत्र।

PROCEDURE OF EXECUTION IN AWARDS PASSED UNDER THE
MOTOR VEHICLE ACT

मोटरयान अधिनियम में पारित अवार्ड के निष्पादन की प्रक्रिया

मोटरयान अधिनियम 1988 सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करने के लिए एक कल्याणकारी कानून है, अतः मोटर दावा अधिकरण अथवा अदालतें वाहन दुर्घटना के मामले में प्रतिकर के अवार्ड की वसूली में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामान्यतः ऐसे अवार्ड का निष्पादन धनराशि की वसूली की डिक्री की भांति किया जाता है। किंतु इसके अलावा भी इस अधिनियम में इस बावत कुछ अतिरिक्त प्रावधान प्रभावी रूप से क्रियान्वयन हेतु समाहित किए गए हैं।

→ मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा पारित अधिनिर्णय के अनुक्रम में प्रतिकर की राशि वसूली हेतु **मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 174** भी अवलोकनीय है, जो इस प्रकार है –

धारा 174 – बीमाकर्ता से धनराशि की बसूली भू राजस्व के बकाया के रूप में करना – जहां किसी अधिनिर्णय के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा कोई रकम देय है, वहां दावा अधिकरण उस रकम के हकदार व्यक्ति द्वारा उसे आवेदन किए जाने पर उस रकम का प्रमाण पत्र कलेक्टर को भेज सकेगा तथा कलेक्टर उसे ऐसी रीति से बसूल करने के लिए अग्रसर होगा, मानो वह भू-राजस्व की बकाया हो।

→ उक्त उपबंध के अनुसार अधिकरण भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली हेतु प्रमाण पत्र (आर.आर.सी.) क्षेत्राधिकार रखने वाले जिले के कलेक्टर को जारी कर सकता है और ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर कलेक्टर द्वारा राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाकर संबंधित अधिकरण में जमा कराई जाएगी और प्रमाणीकरण प्रस्तुत किया जाएगा।

“न धर्मो धर्मात् परो लोके”

There is no greater virtue in the world than righteousness

न्यायालय / मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण म.प्र.

रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट
(अंतर्गत धारा 174 मोटर व्हीकल एक्ट 1988)

प्रति,

कलेक्टर,

जिला..... म.प्र.

विषय क्लेम प्रकरण क्रमांक अवार्ड दिनांक.....से उदभूत
निष्पादन प्रकरण क्रमांक.....में पारित आदेश दिनांक.....के
अनुपालन में डिक्रीदार.....के पक्ष में निर्णितऋणी.....के
विरुद्ध क्षतिपूर्ति धन की राशि.....की वसूली हेतु।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि इस न्यायालय के समक्ष डिक्रीदार..... के द्वारा
क्लेम प्रकरण क्रमांक अवार्ड दिनांक.....में क्षतिपूर्ति की राशि की
वसूली हेतु निष्पादन प्रकरण क्रमांक.....दायर किया है, जिसमें दिनांक..... को
डिक्रीदार के द्वारा धारा 174 मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत निर्णितऋणी से क्षतिपूर्ति की राशि.....
....की वसूली हेतु इस न्यायालय के समक्ष निष्पादन एमजेसी प्रकरण क्रमांक.....प्रस्तुत किया गया
था जिसमें रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कर क्षतिपूर्ति धन की वसूली हेतु दिनांक.....
को आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त राशि भूमि राजस्व के बकाया की भांति वसूली योग्य है।

अतः डिक्रीदार के द्वारा प्रस्तुत आवेदन को दिनांक.....को स्वीकार किया जाकर
धारा 174 एमव्ही एक्ट के अंतर्गत यह आदेश दिया जाता है कि डिक्रीदार.....के पक्ष में
निर्णितऋणी.....के विरुद्ध क्षतिपूर्ति धन की राशि.....की वसूली की
जाकर क्षतिपूर्ति राशि अधिकरण के खाते में जमा कराये।

आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर से व न्यायालय की मुद्रा से जारी।

(न्यायाधीश का नाम)

जिला न्यायाधीश /

सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

जिला म.प्र.

PROCEDURE OF EXECUTION IN ARBITRAL AWARDS PASSED IN ARBITRATION PROCEEDINGS

माध्यस्थम कार्यवाही में पारित माध्यस्थम पंचाट की निष्पादन प्रक्रिया

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम 1996 (अधिनियम 1996) के अंतर्गत माध्यस्थम् (Arbitration) द्वारा पारित “माध्यस्थम पंचाट” (Arbitral Award) के प्रवर्तन के संबंध में प्रवर्तन प्रकरण प्रस्तुत होने पर उसके निष्पादन की प्रक्रिया के विनिर्दिष्ट प्रावधान है।

सामान्यतः जिला न्यायालयों में अधिनियम 1996 के अंतर्गत माध्यस्थम् द्वारा पारित माध्यस्थम् पंचाट के निष्पादन प्रवर्तन प्रकरण प्रस्तुत किए जाते हैं, ऐसे प्रवर्तन प्रकरण के प्रस्तुत होने पर अपनाई जानी वाली प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, इस संबंध में अधिनियम 1996 की धारा 36 अवलोकनीय है, जिसके उपबंध अनुसार अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत माध्यस्थम् पंचाट को अपास्त किए जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पर क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय द्वारा यदि कोई स्थगन नहीं किया गया है, तो धारा 34 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करने हेतु विहित समयावधि के समाप्त होने के पश्चात् धारा 36 के अंतर्गत क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय के समक्ष माध्यस्थम् पंचाट के प्रवर्तन हेतु प्रवर्तन आवेदन प्रस्तुत होने पर न्यायालय द्वारा उसे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के उपबंधों के अनुसार उसे उसी रीति से प्रवर्तित किया जाएगा, मानो वह सिविल न्यायालय की डिक्री हो।

सर्वप्रथम यह समझना आवश्यक है कि इस अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय से क्या आशय है तो इस संबंध में अधिनियम की धारा 2 (ड) अवलोकनीय है, जिसके अनुसार अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम से भिन्न किसी माध्यस्थम् के मामले में कुछ विशेष स्थिति में जहां उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा आरंभिक सिविल अधिकारिता का उपयोग किया जाता है को छोड़कर किसी जिले में आरंभिक अधिकारिता वाला प्रधान सिविल न्यायालय आशयित है। अर्थात् जिले के प्रधान जिला न्यायाधीश एवं ऐसे जिला न्यायाधीश जिन्हें प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा कार्य विभाजन आदेश द्वारा अधिकृत किया गया हो, वे उस जिले के अंतर्गत क्षेत्राधिकार ऐसे प्रवर्तन प्रकरणों में निष्पादन का रखते हैं।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 (अधिनियम 2015) के लागू होने के पश्चात् यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि जहां किसी क्षेत्र विशेष पर क्षेत्राधिकार रखने वाले वाणिज्यिक न्यायालय को अधिसूचित किया गया है वहां किस न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा, तो इस संबंध में न्याय दृष्टांत रिट याचिका कमांक 19656/2020 यशवर्धन रघुवंशी विरुद्ध जिला एवं सत्र न्यायाधीश (डीबी) में पारित आदेश दिनांक 26.02.2021 से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें अधिनियम 2015 की धारा 3 एवं 10 के आलोक में यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि अधिनियम 1996 के अंतर्गत उद्भूत विवादों के संबंध में (अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् द्वारा पारित पंचाट को छोड़कर) प्रस्तुत होने वाले सभी आवेदन या अपील पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार

स्थानीय क्षेत्राधिकारिता रखने वाले अधिसूचित वाणिज्यिक न्यायालय को प्राप्त होगा। जिसमें अधिनियम की धारा 36 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रवर्तन आवेदन भी शामिल हैं। इस न्याय दृष्टांत का पालन किए जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक ए/748 दिनांक 02.03.2021 द्वारा आदेश को राज्य के सभी न्यायालयों को प्रसारित भी किया गया है। इस न्याय दृष्टांत के तथ्यों के अनुसार जिला न्यायालय भोपाल में तीन लाख से एक करोड़ रुपए के मामलों में, जहां प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड को कार्यविभाजन पत्रक द्वारा वाणिज्यिक न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था, उसे माननीय उच्च न्यायालय ने उचित नहीं माना और प्रधान सिविल न्यायालय के रूप में अधिकारिता जिले के प्रधान जिला न्यायाधीश को ही प्राप्त होने से, भले ही मूल्य कुछ भी हो, स्वयं प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अथवा उनके द्वारा अधिकृत अन्य जिला न्यायाधीश द्वारा क्षेत्राधिकार का प्रयोग किए जाने के संबंध में अभिमत भी व्यक्त किया गया है। इस प्रकार यह विधिक स्थिति स्पष्ट होती है कि जहां किसी जिले की स्थानीय सीमाओं पर क्षेत्राधिकार रखने वाले वाणिज्यिक न्यायालय को अधिसूचित किया जा चुका है, वहां तीन लाख रुपए से अधिक मूल्य के मामले, जो वाणिज्यिक मामले की श्रेणी में होते हैं, पर अधिनियम 1996 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकृति के आवेदन या अपील पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार वाणिज्यिक न्यायालय को प्राप्त होगा और जहां वाणिज्यिक न्यायालय अधिसूचित नहीं है, वहां उस जिले के प्रधान जिला न्यायाधीश अथवा उनके द्वारा अधिकृत अन्य जिला न्यायाधीश को ऐसा क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा। अतः तीन लाख रुपए तक के मूल्यांकन के मामलों में ऐसा क्षेत्राधिकार जिले के प्रधान जिला न्यायाधीश अथवा उनके द्वारा अधिकृत जिला न्यायाधीश को ही प्राप्त है।

सामान्यतः जिला न्यायालय में माध्यस्थ पंचाट के प्रवर्तन हेतु अधिनियम 1996 की धारा 36 के अंतर्गत जो प्रवर्तन प्रकरण प्रस्तुत होते हैं, वे धनराशि की वसूली के संबंध में होते हैं। इस प्रकार के प्रवर्तन प्रकरण प्रस्तुत होने पर प्रथम प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि ऐसा प्रवर्तन आवेदन किस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए ?

इस संबंध में न्याय दृष्टांत सुंदरम फाईनेंस लिमिटेड विरुद्ध अब्दुल सावद व अन्य एआईआर 2018 एससी 965 अवलोकनीय है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया है कि प्रवर्तन प्रकरण को निष्पादन हेतु सक्षम न्यायालय को अंतरित करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह न्यायालय जिसके द्वारा निष्पादन किया जाना संभव है, उसके समक्ष सीधे प्रवर्तन प्रकरण प्रस्तुत किया जाकर, उसको प्रवर्तित किए जाने हेतु उपयुक्त कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है।

इस न्याय दृष्टांत में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किये गये हैं, उससे यह स्पष्ट होता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 39 के अंतर्गत माध्यस्थ पंचाट के अंतरण की आवश्यकता नहीं है अर्थात् आदेश 21 नियम 6 सीपीसी में वर्णित प्रक्रिया को अपनाए जाने की आवश्यकता नहीं है और वह न्यायालय जिसके क्षेत्राधिकार में निर्णीत ऋणी की निष्पादन

योग्य संपत्ति स्थित है अथवा निर्णीत ऋणी स्वयं निवास करता है या अभिलाभ के लिए काम करता है या कारोबार करता है, के समक्ष प्रवर्तन प्रकरण प्रस्तुत किया जा सकता है।

अब विचारणीय यह है कि अधिनियम 1996 की धारा 34 के अंतर्गत पंचाट को अपास्त करने के लिए आवेदन किस न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए ?

इस बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा BGS SGS Soma Jv vs NHPC Ltd (2020) 4 SCC 234 में प्रतिपादित सिद्धांत से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें धारा 34 अधिनियम के आवेदन पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार उस न्यायालय को प्राप्त होने के संबंध में अभिमत व्यक्त किया गया है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत उस माध्यस्थ की बैठक का स्थान है, जिसके द्वारा वह पंचाट जिसे अपास्त किए जाने हेतु आवेदन किया गया है, को प्राप्त होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में एक अन्य न्याय दृष्टांत Indus Mobile Distribution Pvt Ltd. Vs Datawind Inovations Pvt Ltd & Ors. (2017) 7 SCC 678 भी अवलोकनीय है।

स्टाम्प ड्यूटी :

यदि अन्य राज्य में स्थित माध्यस्थ द्वारा कोई माध्यस्थ पंचाट पारित किया गया है, तो उस पर स्टांप ड्यूटी की स्थिति क्या होगी ?

इस संबंध में मध्यप्रदेश राज्य में यदि किसी अन्य राज्य में बैठक का स्थान रखने वाले माध्यस्थ द्वारा पारित माध्यस्थ पंचाट के प्रवर्तन हेतु कोई प्रवर्तन आवेदन अधिनियम 1996 की धारा 36 के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है, तो उस पर देय स्टांप ड्यूटी के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ ग्वालियर के द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक न्याय दृष्टांत एमपी नंबर 1872/2020 मैसर्स सुंदरम फायनेंस विरुद्ध मुकेश पाराशर में पारित आदेश दिनांक 08 अगस्त 2024 से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने भारतीय स्टांप अधिनियम की धारा 19 ए व 33 तथा अधिनियम 1996 की धारा 36 के उपबन्धों को विचार में लेकर पंचाट की राशि पर 02 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी देय होने का अभिमत व्यक्त किया है और जो स्टांप ड्यूटी पूर्व से संदाय है उससे अतिरिक्त स्टांप ड्यूटी ही संदाय की जानी है।

"श्रद्धावान् लभते ज्ञानम्"

श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है।

EXECUTION OF DECREE FOR SPECIFIC PERFORMANCE OF THE CONTRACT

संविदा के विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री का निष्पादन

संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन की डिक्री के निष्पादन की रीति आदेश 21 नियम 32 सिविल प्रक्रिया संहिता में विहित है, जिसके अनुसार—

1. जहां उस पक्षकार को, जिसके विरुद्ध संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिये कोई डिक्री पारित की गई है, उस डिक्री के आज्ञानुवर्तन के लिये अवसर मिल चुका है और उसका आज्ञानुवर्तन करने में यह जानबूझकर असफल रहा है, वहां वह डिक्री संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिये डिक्री की दशा में सिविल कारागार में उसके निरोध या उसकी संपत्ति की कुर्की द्वारा, या दोनों रीति से प्रवृत्त की जा सकेगी।
2. जहां वह पक्षकार जिसके विरुद्ध विनिर्दिष्ट पालन के लिये डिक्री पारित की गई है, कोई निगम है, वहां डिक्री उस निगम की संपत्ति की कुर्की द्वारा या न्यायालय की इजाजत से उसके निदेशकों या अन्य प्रधान अधिकारियों के सिविल कारागार में निरोध द्वारा या कुर्की और निरोध दोनों रीति से प्रवृत्त की जा सकेगी।
3. जहां उपनियम 1 या उपनियम 2 के अधीन की गई कोई कुर्की 6 मास के लिये प्रवृत्त रह चुकी है वहां यदि निर्णीतऋणी ने डिक्री का आज्ञानुवर्तन नहीं किया है और डिक्रीदार ने कुर्क की गई संपत्ति का विक्रय किये जाने के लिए आवेदन किया है तो ऐसी संपत्ति का विक्रय किया जा सकेगा और आगमों में से न्यायालय डिक्रीदार को ऐसा प्रतिकर दे सकेगा जो वह ठीक समझे और बाकी (यदि कोई हो) निर्णीतऋणी के आवेदन पर उसे देगा (और न्यायालय भी, दर्शित किए गए उपयुक्त हेतुक से कुर्की के समय में विस्तार कर सकेगा, जो एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए प्रवर्तन में रहेगा।)
4. जहां निर्णीतऋणी ने डिक्री का आज्ञानुवर्तन कर दिया है और उसका निष्पादन करने के लिए सभी खर्चों का संदाय कर दिया है, जिनका संदाय करने के लिए वह आबद्ध है या जहां कुर्की की तारीख से 6 मास के (या ऐसे अतिरिक्त समय जिसे न्यायालय ने उपनियम (3) के अधीन नियत किया है) का अंत होने तक संपत्ति के विक्रय किये जाने के लिये कोई आवेदन नहीं किया गया या किया गया है तो नामंजूर कर दिया गया है, वहां कुर्की नहीं रह जायेगी।
5. जहां संविदा के विनिर्दिष्ट पालन की किसी डिक्री का आज्ञानुवर्तन नहीं किया गया है, वहां न्यायालय पूर्वोक्त सभी आदेशिकाओं के या उनमें से किसी के भी बदले या उनके साथ-साथ निदेश दे सकेगा कि वह कार्य, जिसके किये जाने की अपेक्षा की गई थी, जहां तक हो सके, डिक्रीदार या न्यायालय द्वारा नियुक्त किये गये किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निर्णीतऋणी के खर्च पर किया जा सकेगा और कार्य कर दिये जाने पर जो व्यय उपगत हुए हों वे ऐसी रीति से अभिनिश्चित किये जा सकेंगे जो न्यायालय निर्दिष्ट करें और इस प्रकार वसूल किये जा सकेंगे मानों वे डिक्री में ही सम्मिलित हों।

नोट:— उक्त प्रावधान व्यादेश के लिये पारित डिक्री के संबंध में भी लागू होते हैं।

आदेश 21 नियम 32 (1) सी.पी.सी. के अधीन डिक्री का निष्पादन अनुज्ञात करने के पूर्व न्यायालय को इस संबंध में संतुष्ट होना आवश्यक है कि निर्णीतऋणी के पास डिक्री के पालन का अवसर था, लेकिन वह जान-बूझकर उसका पालन करने में असफल रहा है। प्रत्येक मामले में यह तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर विनिश्चित किया जायेगा कि क्या निर्णीतऋणी के पास डिक्री के पालन

का अवसर था या नहीं। यह साबित होना आवश्यक है कि निर्णीतऋणी द्वारा की गई अवज्ञा या असफलता जान-बूझकर, विमर्शित या आशयित थी।

संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन की डिक्की का निष्पादन सिविल कारागार में निरोध द्वारा, निर्णीतऋणी की संपत्ति की कुर्की द्वारा अथवा कुर्की एवं सिविल कारागार में निरोध द्वारा तथा कुर्क संपत्ति के विक्रय द्वारा की जा सकेगी।

न्यायालय आदेश 21 नियम 34 में वर्णित रीतियों के साथ-साथ या उनके स्थान पर यह निर्देश भी दे सकता है कि विक्रय पत्र के निष्पादन की कार्यवाही डिक्कीधारी द्वारा अथवा न्यायालय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकेगा, जिसका खर्च निर्णीतऋणी से वसूलनीय होगा। जहां विक्रय पत्र निष्पादित किये जाने की डिक्की पारित की गई है तथा डिक्कीधारी द्वारा प्रतिफल का संदाय निर्णीतऋणी को कर दिया गया है या न्यायालय में जमा कर दिया गया है और निर्णीतऋणी विक्रय पत्र का निष्पादन नहीं कर रहा वहां पर न्यायालय डिक्कीधारी एवं निर्णीतऋणी के डिक्की के निबंधनों के अनुसार दस्तावेज का प्रारूप तैयार करने का अवसर देने के उपरान्त विहित प्रारूप में दस्तावेज का निष्पादन करेगा, जिसका वही प्रभाव होगा, जो निर्णीतऋणी द्वारा निष्पादित करने पर होता है।

विक्रय पत्र के निष्पादन की प्रक्रिया निम्नानुसार की जावेगी—

1. निर्णीतऋणी द्वारा विक्रय पत्र का निष्पादन अस्वीकार किये जाने पर सर्वप्रथम डिक्कीधारी डिक्की की शर्तों के अनुसार विक्रय पत्र का प्रारूप तैयार कर निष्पादन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
2. यह प्रारूप सिविल प्रक्रिया संहिता के परिशिष्ट—ड. संख्यांक 10 की सूचना के साथ निर्णीतऋणी पर निर्वाह कराया जायेगा, जिसमें उसे निर्देशित किया जायेगा कि यदि प्रारूप के संबंध में कोई आपत्ति है तो वह न्यायालय द्वारा नियत समय के भीतर आपत्ति प्रस्तुत करे।
3. यदि ऐसी कोई आपत्ति प्रस्तुत की जाती है तो न्यायालय उसका निराकरण करेगा तथा आवश्यकतानुसार विक्रय के प्रारूप में परिवर्तन किया जावेगा। यदि ऐसी कोई आपत्ति लिखित रूप से निर्णीतऋणी द्वारा प्रस्तुत नहीं की जाती और न्यायालय ऐसे प्रारूप दस्तावेज के अनुसार दस्तावेज का निष्पादन कर देता है तो वह अंतिम होगा और पूर्व न्याय के रूप में प्रवर्तित होगा। यह उल्लेखनीय है कि निर्णीतऋणी केवल प्रारूप दस्तावेज के संबंध में ही आपत्ति कर सकता है, डिक्की की प्रकृति के संबंध में नहीं।
4. उक्त विक्रय पत्र/दस्तावेज पर जो स्टॉप शुल्क देय होगा, वह डिक्कीधारी को स्टॉप अधिनियम के प्रावधान अनुसार अदा करना पड़ेगा। **(माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय ने श्रीमती हरविंदर कौर वि० म.प्र. राज्य ए.आई.आर. 2007, एम.पी. 86 में यह प्रतिपादित किया है कि दस्तावेज, जिस दिनांक को पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया है, उस दिनांक को संपत्ति के बाजार मूल्य पर निर्धारित स्टॉप शुल्क देय होगा)**
5. यदि, निर्णीतऋणी दस्तावेज का निष्पादन करने से इंकार कर देता है तो न्यायाधीश स्वयं या उसकी ओर से नियुक्त अधिकारी द्वारा निष्पादित किया जावेगा।
6. दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन न्यायालय स्वयं या उसकी ओर से अधिकृत किसी अनुसचिवीय कर्मचारी द्वारा संपादित किया जावेगा।

संविदा के विनिर्दिष्ट पालन की डिक्की के निष्पादन में आधिपत्य की स्थिति—

यदि डिक्की में आधिपत्य प्रदान किये जाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है तो भी ऐसी डिक्की का निष्पादन करते समय निष्पादन न्यायालय डिक्कीधारी को संपत्ति पर आधिपत्य प्रदान कर सकता

है क्योंकि ऐसी डिक्री में आधिपत्य अंतर्निहित होता है। इस संबंध में **न्याय दृष्टांत मो. याकूब वि० अब्दुल रउफ 2002 (1) एम.पी.एच.टी. 216** अवलोकनीय है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि यदि धारा 47 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निष्पादन न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई आपत्ति प्रस्तुत की जाती है कि मूल दावे में स्थावर संपत्ति के आधिपत्य का अनुतोष नहीं मांगा गया, इस कारण निष्पादन न्यायालय आधिपत्य प्रदान नहीं कर सकता तो ऐसी आपत्ति प्रचलनशील नहीं है क्योंकि इस संबंध में **माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्याय दृष्टांत बाबूलाल वि० मे. हजारीलाल किशोरीलाल ए.आई.आर. 1982 एस.सी. 818** में यह स्पष्ट किया है कि “जहां संविदा के दूसरे पक्ष के पास वाद ग्रस्त संपत्ति का अनन्य कब्जा है वहां विनिर्दिष्ट रूप से आधिपत्य प्रदान किये जाने के अनुतोष की याचना किए बिना मात्र विक्रय की संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन डिक्रीधारी को पूर्ण एवं प्रभावी अनुतोष प्रदान कर सकता है। निर्णीत ऋणी, डिक्री की पूर्णतः संतुष्टि हेतु न केवल विक्रय पत्र संपादित करने बल्कि संपत्ति का आधिपत्य प्रदान करने हेतु आबद्ध है, विक्रय की संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन के सभी मामलों में आधिपत्य के अनुतोष की याचना करना आवश्यक नहीं है।

यद्यपि **विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 22** में जो प्रावधान है, उसके अनुसार स्थावर संपत्ति के अंतरण की संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के दावे में कोई ऐसा अनुतोष न्यायालय द्वारा दावाकर्ता को नहीं दिया जायेगा, जिसका उसने दावा नहीं किया हो, किंतु उक्त प्रावधान ऐसे मामले में लागू होता है, जिसमें आधिपत्य का अनुतोष तब तक प्रभावी रूप से प्रदान नहीं किया जा सकता, जब तक कि उसका विनिर्दिष्ट रूप से दावा न किया गया हो। जैसे, जहां संविदा के अधीन संपत्ति प्रतिवादी तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से धारित की गई हो अथवा वादी तथा प्रतिवादी के मध्य विक्रय की संविदा संपन्न होने के पश्चात् संपत्ति का आधिपत्य तीसरे पक्षकार के पास चला गया हो। ऐसे मामलों में आधिपत्य के अनुतोष को विनिर्दिष्ट रूप से अभिवचनित किया जाना आवश्यक है।

स्थावर संपत्ति के आधिपत्य के डिक्री के निष्पादन की रीति—

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 नियम 35 एवं 36 के अनुसार स्थावर संपत्ति के आधिपत्य की डिक्री का निष्पादन वास्तविक अथवा भौतिक आधिपत्य के परिदान तथा औपचारिक, प्रतीकात्मक अथवा प्रलक्षित आधिपत्य के परिदान द्वारा किया जा सकेगा, जिसके संबंध में आधिपत्य के परिदान का वारंट परिशिष्ट ड. के प्रारूप 11 के अनुरूप जारी किया जाता है।

यह उल्लेखनीय है कि वास्तविक आधिपत्य प्रदान किये जाने हेतु संपत्ति की पहचान सुनिश्चित होना आवश्यक है और यदि ऐसी पहचान नहीं हुई है तो निष्पादन न्यायालय संपत्ति की पहचान सुनिश्चित करने के लिये संक्षिप्त जांच कर सकता है अथवा डिक्री की शर्तों के अनुसार कमिश्नर नियुक्त करके भी संपत्ति की पहचान की जा सकती है। इस संबंध में **न्याय दृष्टांत रविन्दर कौर विरुद्ध अशोक कुमार ए.आई.आर. 2004 एस.सी. 904** अवलोकनीय है।

"Executio Juris Non Habet Injuriam"
The Execution of Law does no injury

EXECUTION IN A PARTITION SUIT:

Normally, we have two decrees:

Preliminary Decree: For declaring the divisible rights of each party in the joint property.

Final Decree: For specifying the share and putting each party in possession of his specific share.

Shub Karan Bubna alias Shub Karan Prasad

Bubna v. Sita Saran Bubna and others,

(2009) 3 SCC 689

The Hon'ble Supreme Court of India,

while considering the concept of final decree in a partition suit, has held:

It is different from an application for a final decree in mortgage suit and has mandated that after passing of a preliminary decree in a suit for partition, the proceedings should be continued by the Trial Court till final decree is passed.

The relevant observations and directions issued are extracted as follows:

1. In a partition suit, preliminary decree only decides a part of the suit and therefore an application for final decree is an application seeking further progress in a pending suit.
2. In partition suit,
 - a. there can be a preliminary decree followed by a final decree, or
 - b. there can be a decree which is a combination of preliminary decree and final decree or
 - c. there can be merely a single decree with certain further steps to be taken by the court.
3. In fact, several applications for final decree are permissible in a partition suit. A decree in a partition suit is for the benefit of all the co-owners and therefore, it is said that there is really no judgment debtor in a partition decree.
4. A preliminary decree for partition only identifies the properties to be subjected to partition, defines and declares the shares/rights of the parties.
5. The prayer relating to actual division by metes and bounds and allotment is to be done under the final decree proceedings.
6. Thus the application for final decree is to be considered an application in a pending suit for granting the relief of actual partition.
6. Therefore, the concept of final decree in a partition suit is different from the concept of final decree in a mortgage suit.
7. Consequently an application for a final decree in a mortgage suit is different from an application for final decree in partition suits.
8. Initiation of final decree proceedings does not depend upon an application for final decree for initiation.
9. The Code also does not contemplate filing of an application for final decree. Therefore, when a preliminary decree is passed in a partition suit, the proceedings should be continued by fixing dates for further proceedings till a final decree is passed.
10. It is the duty and function of the court. Performance of such function does not require a reminder from the litigant. The mindset should be to expedite the process of dispute resolution.

**Kattukandi Edathi Krishnan and Another v.
Kattukandi Edathil Valsan and Others, 2022 SCC
OnLine SC 737,**

Hon'ble S.C reiterated the earlier observations and held :-

1. Once a preliminary decree is passed by the Trial Court, the court should proceed with the case for drawing up the final decree suo motu.
2. After passing preliminary decree, the Trial Court has to list the matter for taking steps under Order 20 Rule 18 of the CPC. The courts should not adjourn the matter sine die.
3. There is also no need to file a separate final decree proceedings. In the same suit, the court should allow the party to file an appropriate application for drawing up the final decree. The suit comes to an end only when a final decree is drawn. Relevant partition regarding final decree in partition suit

Order 20 Rule 18 CPC

- (a) - Decree in suit for partition of property or separate possession of a share therein- Where the Court passes a decree for the partition of property or for the separate possession of a share therein, then -

- 1- If and in so far as the decree relates to an estate assessed to the payment of revenue to the Government, the decree shall declare the rights of the several parties interested in the property, but shall direct such partition or separation to be made by the Collector, or any gazetted subordinate of the Collector deputed by him in this behalf, in accordance with such declaration and with the provisions of section 54;
- 2- If and in so far as such decree relates to any other immovable property or to movable property, the Court may, if the partition or separation cannot be conveniently made without further inquiry, pass a preliminary decree declaring the right of the several parties interested in the property and giving such further directions as may be required.

- (b)- **Relevant Provisions Under Partition Act 1893**

1. THE PARTITION ACT, 1893

SECTIONS

1. **Title, extent and saving.**
2. **Power to court to order sale instead of division in partition suits.**
3. **Procedure when sharer undertakes to buy.**
4. **Partition suit by transferee of share in dwelling-house.**
5. **Representation of parties under disability.**
6. **Reserved bidding and bidding by shareholders.**
7. **Procedure to be followed in case of sales.**
8. **Orders for sale to be deemed decrees.**
9. **Saving of power to order partly partition and partly sale.**
10. **Application of Act to pending suits.**
2. Power to court to order sale instead of division in partition suits. Whenever in any suit for partition in which, if instituted prior to the commencement of this Act, a decree for partition might have been made, it appears to the court that, by reason of the nature of the property to which the suit relates, or of the number of the shareholders therein, or of any other special circumstance, a division of the property cannot reasonably or conveniently be made, and that a

sale of the property and distribution of the proceeds would be more beneficial for all the shareholders, the court may, if it thinks fit, on the request of any of such shareholders interested individually or collectively to the extent of one moiety or upwards, direct a sale of the property and a distribution of the proceeds.

3. Procedure when sharer undertakes to buy.

- (1) If, in any case in which the court is requested under the last foregoing section to direct a sale, any other shareholder applies for leave to buy at a valuation the share or shares of the party or parties asking for a sale, the court shall order a valuation of the share or shares in such manner as it may think fit and offer to sell the same to such shareholder at the price so ascertained, and may give all necessary and proper directions in that behalf.
- (2) If two or more shareholders severally apply for leave to buy as provided in sub-section (1), the court shall order a sale of the share or shares to the shareholder who offers to pay the highest price above the valuation made by the court.
- (3) If no such shareholder is willing to buy such share or shares at the price so ascertained, the applicant or applicants shall be liable to pay all costs of or incident to the application or applications.

4. Partition suit by transferee of share in dwelling-house.-

- (1) Where a share of a dwelling-house belonging to an undivided family has been transferred to a person who is not a member of such family and such transferee sues for partition, the court shall, if any member of the family being a shareholder shall undertake to buy the share of such transferee, make a valuation of such share in such manner as it thinks fit and direct the sale of such share to such shareholder, and may give all necessary and proper directions in that behalf.
- (2) If in any case described in sub-section
 - (1) two or more members of the family being such shareholders severally undertake to buy such share, the court shall follow the procedure prescribed by sub-section
 - (2) of the last foregoing section.

5. Representation of parties under disability. In any suit for partition a request for sale may be made or an undertaking, or application for leave, to buy may be given or made on behalf of any party under disability by any person authorised to act on behalf of such party in such suit, but the court shall not be bound to comply with any such request, undertaking or application unless it is of opinion that the sale or purchase will be for the benefit of the party under such disability.

6. Reserved bidding and bidding by shareholders.

- (1) Every sale under section 2 shall be subject to a reserved bidding, and the amount of such bidding shall be fixed by the court in such manner as it may think fit and may be varied from time to time.
- (2) On any such sale any of the shareholders shall be at liberty to bid at the sale on such terms as to non-payment of deposit or as to setting off or accounting for the purchase-money or any part thereof instead of paying the same as the court may seem reasonable.
- (3) If two or more persons, of whom one is a shareholder in the property, respectively advance the same sum at any bidding at such sale, such bidding shall be deemed to be the bidding of the shareholder.

7. Procedure to be followed in case of sales. Save as hereinbefore provided, when any property is directed to be sold under this Act, the following procedure shall, as far as practicable, be adopted, namely :-
 - (a) if the property be sold under a decree or order of any other court, such procedure as the High Court may from time to time by rules prescribe in this behalf, and until such rules-art made the procedure prescribed in the Code of Civil Procedure in respect of sales in execution of decrees.
8. Orders for sale to be deemed decrees. Any order for sale made by the court under section 2, 3 or 4 shall be deemed to be a decree within the meaning of section 2 of the Code of Civil Procedure (14 of 1882).
9. Saving of power to order partly partition and partly sale. In any suit for partition the court may, if it shall think fit, make a decree for a partition of part of the property to which the suit relates and a sale of the remainder under this Act.
10. Application of Act to pending suits. This Act shall apply to suits instituted before the commencement thereof, in which no scheme for the partition of the partition has been finally approved by the court.

For Preparing final decree mode adapted be Courts :-

- (a) Through Sale Amin with/without help of Revenue department.
- (b) Through Ld Advocate Commissioner.
- (c) Through any person/expert

In **Writ petition No. 1396 of 2015(M/S), Dr. Sudesh bala Vs. Dr. Santosh Singh, dated 18.06.2015 High Court of Uttarakhand** it is observed that – It is clear from from the said provision that for conducting a scientific survey, any person who has the expertise, may be directed to conduct said survey and the word person used in the provision is inclusive of an institution. The view that any person competent to conduct a scientific survey can be appointed by the court. court for supervising the construction of partition wall and staircase on the disputed property by the superintending engineer, P.W.D., so that the disputed property stand divided in two equal parts is correct in light of Order 26 Rule 13. C.P.C. for partition of immovable property and that the survey can be issued to be done by any person to whom the court deems fit to effect the partition of said property.

"Interest Reipublicae Ut Sit Finis Litium"

It is in the interest of the state that there be an end to litigation.

EXECUTION CONCERNING RECOVERY OF POSSESSION OF IMMOVABLE PROPERTY

Execution of a decree under the M.P. Accommodation Control Act 1961 is governed by this act's provision and the code of civil procedure, specifically order 21 of CPC

Once a civil court grants a remedy through a decree, it is essential that the court ensures its proper implementation. The enforcement of such decrees forms the backbone of the civil justice system. The overall effectiveness and credibility of civil litigation heavily rely on how successfully court decrees are executed. To this end, the legislature has laid down detailed and comprehensive provisions within the Code of Civil Procedure (CPC) to guide the process of execution. Specifically, Order XXI comprises 106 rules dealing with various aspects of execution, complemented by Sections 36 to 74 of the CPC.

In civil disputes, particularly those involving landlord-tenant conflicts and property matters, the enforcement of eviction decrees and the handover of vacant possession is a key component. The aim is to ensure that the decree-holder gains rightful possession of the property, while also providing a fair chance for the judgment debtor and any third parties to raise legitimate objections.

Decree Regarding Immovable Property:

The effective implementation of eviction decree and the procedures for handing over vacant possession—as well as the mechanisms for raising objections—are regulated through multiple provisions contained in the Code of Civil Procedure, 1908.

1. ORDER XXI RULE 35 CPC:

Decree for Immovable Property:

When a court issues a decree directing the delivery of immovable property, the execution is carried out by transferring possession to the decree-holder. If someone who is obligated under the decree refuses to vacate the premises, they may be removed to ensure compliance.

Order XXI Rule 36 of the CPC:

Execution of Decree for Immovable Property – When Occupied by a Tenant:

A significant factor in execution proceedings is the presence of tenants or other lawful occupants. In such cases, rather than forcibly evicting the occupant, possession is considered delivered by affixing a copy of the warrant at a prominent location on the property and announcing the decree to the occupants, following the procedure laid down under Order XXI Rule 36 of the Code of Civil Procedure.

Although Rules 35 and 36 of Order XXI both pertain to decrees involving immovable property, they serve different purposes. Rule 35 primarily concerns actual or physical possession (as stated in sub-rules 1 and 3), whereas Rule 36 deals with symbolic or formal possession (as described in sub-rule 2 and Rule 36).

According to Rule 35 of Order XXI, when a decree orders the handover of immovable property, actual possession must be given to the decree-holder or a person designated by them, and if needed, by evicting any party bound by the decree who refuses to vacate. In cases where a decree grants joint possession of immovable property, the court ensures compliance by posting a copy of the warrant in a clearly visible location on the property and publicly announcing the substance of the decree traditionally by beating a drum or using another customary method at a suitable location. If possession is to be handed over for a building or enclosed space, and the occupant despite being obligated under the decree denies access, the court may intervene through its officers. After providing adequate notice and allowing time for any women observing traditional customs to withdraw, the officers may unlock, unbolt, or force open doors, or take any other necessary steps to enable the decree-holder to take possession. This rule outlines how possession should be granted. For vacant plots of land, the court is empowered to order the removal or demolition of any structures that may have been erected during the litigation period.

CHALLENGES, HURDLES AND SOLUTION

1) *Hurdles faced in execution when the property is occupied by a Tenant and the Decree is passed against the Landlord, Along with Constructions Made during the Course of Litigation.*

One of the primary difficulties encountered during the enforcement of possession decrees arises when the property is occupied by a tenant, while the decree has been passed solely against the landlord. In such cases, execution becomes complex because the tenant, who is not a party to the decree, continues to retain lawful possession. Since the court's order is enforceable only against the judgment-debtor (the landlord), the decree-holder may face legal and procedural obstacles in obtaining actual possession of the property.

When a decree is passed for the delivery of immovable property that is currently under the possession of a tenant or another person lawfully entitled to occupy the property—and who is not legally obligated by the decree to vacate—the court is required to execute symbolic possession. This is done by affixing a copy of the warrant in a prominent location on the property and publicly announcing the contents of the decree by beating a drum or using another traditional method in a suitable public place. In scenarios where the property has been leased for construction or subletting purposes, and an eviction decree is later granted to the landlord, complications may arise if tenants were inducted during the pendency of the suit without the court's permission. It is a settled legal principle that tenants who claim possession through or under the judgment-debtor are deemed to be bound by the decree. Hence, even if such tenants were not impleaded in the suit, their eviction can be sought, and their resistance does not amount to a legal bar to the execution of the decree.

The Hon'ble Supreme Court in **B. GANGADHAR Vs. B.G. RAJALINGAM (AIR 1996 SUPREME COURT 780)** clarified the scope of the executing court's powers under Order 21 Rule 35(3) of the Code of Civil Procedure:

“...in view of Order 21, Rule 35(3) the Court executing the decree is entitled to pass such incidental, ancillary or necessary orders for effective enforcement of the decree for possession. That power also includes the power to remove any obstruction or superstructure made pendente lite. The exercise of incidental, ancillary or inherent power is consequential to deliver possession of the property in execution of the decree. Thus where in a suit for declaration of title and vacant possession of land, the decree was passed by the trial Court directing handing over vacant possession of land by demolishing the shops constructed by the Judgment debtor during pendency of suit, the said direction in execution of decree was not without jurisdiction.”

This decision confirms that the executing court is fully empowered to order removal of any obstructions or constructions carried out during the pendency of a suit—even in the absence of a specific prayer for mandatory injunction—if such action is necessary to hand over possession as per the decree.

Similarly, the Hon'ble High Court of Judicature at Andhra Pradesh addressed the issue in **DONGALA VENKAIAH AND ANOTHER Vs. DONGALA RAJI REDDY (2007 (5) ALD 716)**. The court ruled:

“Execution of decree under Order 21 Rules 35, 97 and 101 C.P.C in a suit for declaration of title and recovery of possession is decreed and Structures like residential houses made by Judgment Debtors/Defendants in suit land, the Trial Court ordered execution directing Bailiff to demolish construction and handover vacant possession of land to decree holder is Not without jurisdiction. Merely because plaintiff has not sought for relief of mandatory injunction, it cannot be said that decree is inexecutable and it is of no consequence whether structures existing on suit land were constructed prior to or after filing of suit.”

“Suit filed for recovery of possession of land and Having filed written statement, defendants did not let in evidence and if suit decreed and Execution Petition for execution of decree filed. Defendants instead of filing appeal, filed suit for cancellation of said decree and Defendants' suit was dismissed and When

Bailiff could not execute warrant for delivery of possession of suit land on account of existence of residential houses, Decree holder filed Execution application . under Order 21 Rule 97 of C.P.C. requesting Court to give directions to bailiff to demolish constructions made by defendants (Judgment debtors) in suit land and such Directions were issued accordingly overruling Judgment debtors objections and Contention that without a prayer and decree for mandatory injunction, trial Court cannot direct bailiff to remove structures/residential houses and as the structures/residential buildings were already in existence even at time of institution of suit and plaintiff failed to ask for a decree for mandatory injunction, executing Court cannot order delivery of vacant possession.”

“Rejecting contention that if such constructions were made only during the pendency of the suit then the plaintiff can execute the decree without tortuous remedy of separate suit seeking mandatory injunction or possession, the Court held.”

These rulings emphasize that the executing court retains the authority to ensure delivery of vacant possession by directing demolition of unauthorized structures created during litigation, even if the original decree did not contain an explicit direction for mandatory injunction.

However, an important exception applies when **sub-tenants**, not impleaded as parties to the original suit, are in occupation. If such occupants are not rank trespassers and were inducted into possession without being part of the litigation—and their impleadment was actively opposed—they are not bound by the eviction decree. In such cases, the court is limited to granting **symbolic possession** only and cannot proceed with actual eviction against non-party sub-tenants.

2) *Objections under Section 47 and Order XXI Rules 97, 99, and 101 of the Civil Procedure Code (CPC).*

One of the primary obstacles in enforcing a decree issued by a civil court is the objections raised during execution proceedings—these objections may come from the judgment-debtor, third parties, or those claiming rights through or under the judgment-debtor. Typically, such objections are filed under Section 47 and Order XXI Rules 97, 99, and 101 of the Civil Procedure Code (CPC). If the obstruction is by someone who is bound by the decree, the decree-holder may seek redress under Rule 35(3). However, if a third party creates the obstruction, the appropriate procedure is to apply under Rule 97.

Section 47 CPC specifically deals with questions that must be addressed by the executing court. Initially, the section had three sub-sections, but following the Amendment Act No. 104 of 1976, effective from 1st February 1977, sub-section (2) was removed. The current version includes two sub-sections and two explanations:

Any issues arising between the original parties to the suit (or their legal successors) that relate to execution, satisfaction, or discharge of the decree are to be decided by the court executing the decree itself—not by a separate civil suit. If the question concerns whether someone qualifies as a representative of a party, the executing court must determine it for the purposes of this section.

Explanation I clarifies that "parties to the suit" includes both the plaintiff (even if the suit is dismissed) and the defendant (even if the decree goes against them).

Explanation II states:

- (a) A purchaser of the decree is considered a party to the original suit.
- (b) Any matter concerning delivery of possession to such a purchaser or their representative is treated as related to the execution, discharge, or satisfaction of the decree.

In **Rahul S. Shah Vs. Jitendra Kumar Gandhi reported in 2021(2) JLJR (SC) 459**, the Hon'ble Supreme Court ruled that courts should not routinely entertain execution objections filed by third parties. If such applications were previously dealt with during the trial, they should not be reexamined without justification. Evidence during execution should only be allowed in rare situations where factual disputes cannot be resolved through quicker means, such as appointing a commissioner or relying on

digital evidence with affidavits. If the court finds that objections are baseless or made in bad faith, it may proceed under Rule 98(2) of Order XXI and may also award compensatory costs under Section 35-A. Moreover, under Section 60, if the property is held in the name of the judgment-debtor or by someone holding it in trust for him, it should be broadly interpreted to include persons from whom the judgment-debtor can derive benefits. Therefore, before registering such an application, the court should conduct a preliminary hearing. If no merit is found, the application should be rejected at the threshold itself.

The types of issues that fall under Section 47 are those that could arise properly in the course of execution between the parties or their representatives. It is critical to note the well-settled principle that "the executing court cannot go behind the decree." This means that the court cannot reassess the factual or legal correctness of the decree—it must enforce it as it stands.

In **Pains VS Sant Ram AIR 1970 SC 1475**, the Supreme Court held that Section 47 does not authorize the executing court to examine the validity of the decree if no illegality appears on its face.

Generally, three main types of objections are permissible under Section 47:

- (A) Decrees passed against a deceased individual;
- (B) Decrees that are vague or ambiguous;
- (C) Decrees passed without jurisdiction.

Multiple court decisions have confirmed that a judgment-debtor may argue that a decree is void under this section, but such a claim must relate to a jurisdictional defect rendering the decree a nullity. The executing court is not empowered to review the correctness or legality of the decree unless it is inherently void. The term "representative" used in Section 47 is broader than "legal representative." It includes anyone who steps into the shoes of a party, handles their property, or to whom rights or obligations have been assigned, transferred, or devolved. Thus, heirs, executors, administrators, and transferees all qualify as representatives under this section.

Additionally, any questions about handing over possession to a purchaser or their representative fall within the scope of execution, discharge, or satisfaction of the decree. Under Order XXI Rule 16 CPC, a decree can be executed by someone who has legally acquired it—making such transferees “representatives” of the decree-holder under Section 47. Therefore, the executing court is empowered to adjudicate all issues concerning the execution, discharge, or satisfaction of the decree between the original parties and their representatives but it cannot go beyond this mandate.

In Awadh Bihari Tewari Vs Narain Tewari - AIR 1961 Pat 427 at pages 433–434, it was held:

“The validity of the decree can be challenged in execution proceedings only on the ground that the court which passed the decree was lacking in inherent jurisdiction in the sense that it could not have jurisdiction of the case because the subject matter was wholly foreign to its jurisdiction or that the defendant was dead at the time of the suit had been instituted or decree passed, or some other grounds which could have the effect of rendering the court entirely lacking in jurisdiction in respect of the subject - matter of the suit or over the parties to it.”

Similarly, in **Vasudev Dhanjibhai Modi Vs. Rajabhat Abdul Rahman AIR 1970 SC 1475**, the Supreme Court observed:

“...when a decree is nullity, for instance, where it is passed without bringing the legal representatives on the record of a person who is dead at the date of decree is sought to be executed an objection in that behalf may be raised in a proceeding for execution. Again when a decree is made by a court which has no inherent jurisdiction to make it, objection as to its validity may be raised in an execution proceeding if the objection appears in the face of the record. When the matter of jurisdiction not appear on the face of the record and requires examination of the question raised and decided at the trial or which could

have been but have not been raised, the executing court will have no jurisdiction to entertain an objection as to the validity of the decree even on the ground of absence of jurisdiction.”

In **Haryana Vidyut Prasaran Nigam Ltd. Vs. Gulshan Lal (2009) 13 SCC 354**, it was held that:

“An objection under Section 47 of the Code of Civil Procedure when filed by the judgment debtor it is incumbent upon him to show that the decree was ex-facio nullity. For the said purpose, the court is precluded from making in depth scrutiny as regards the entitlement of the plaintiff with reference to not only his claim made in the plaint, but also the defense set up by the judgment debtor. As the judgment of the trial court could have not been reopened, the correctness thereof could not have been put in question.”

Further, in **Pratibha Singh Vs. Shanti Devi (2003) 2 SCC 330**, the Hon’ble Supreme Court, while explaining the scope of Section 47, held:

“...when the suit as to immovable property has been decreed and the property is not definitely identified, the defect in the court record caused by overlooking of provisions contained in Order VII Rule 3, in Order XX Rule 3 is capable of being cured. After, all a successful plaintiff should not be deprived of the fruits of the decree. Resort can be had to Section 152 or Section 47 of the Code of Civil Procedure depending on the facts and circumstances of each case which of two provision be more appropriate, just and convenient to invoke. Being an inadvertent error not effecting the merit of the case, it may be corrected under Section 152 CPC by the court which passed the decree by supplying the omission. Alternatively, the exact description of decretal property may be ascertained, by the executing court as a question relating to execution, discharge or satisfaction of the decree within the meaning of this Section. A decree of a competent court should not be allowed to be defeated on account of an accidental slip or omission, we think it would be more appropriate to invoke Section 47 CPC.”

3) Resistance to Execution / Resistance to Delivery of Possession to Decree-Holder or Purchaser

(Section 74 and Rules 97 to 103 of Order XXI of the CPC)

If the court determines that the decree-holder (who has obtained a decree for possession of immovable property) or the purchaser (who acquired such property through court sale) is being hindered or resisted from taking possession—either by the judgment-debtor or someone acting on their behalf—and that such resistance has no valid basis, the court may, upon application by the decree-holder or purchaser, order that the person causing such obstruction be detained in civil prison for up to 30 days. Additionally, the court can direct that possession of the property be handed over to the decree-holder or purchaser.

Order XXI Rule 97 – Resistance or Obstruction to Possession of Immovable Property

1. If a decree-holder or purchaser is prevented or obstructed by any person from obtaining possession of the property, they may approach the court by filing an application outlining the nature of the resistance or obstruction.
2. Upon receiving such an application, the court is obligated to examine and decide the matter under the provisions set out in the CPC.

This rule allows not only the decree-holder but also any affected party to bring resistance or obstruction issues before the court. If the obstruction is unreasonable and instigated by the judgment-debtor, the court has the authority—after inquiry—to order removal of such resistance and take suitable action.

In **Brahmadeo Choudhary Vs. Rishikesh Prasad Jaiswal AIR 1997 SC 856**, the Hon’ble Supreme Court ruled that the executing court may assess objections filed by a third party against a possession warrant. The court further held that even before being dispossessed, an objector is entitled to have their rights adjudicated under Rule 97.

This interpretation was affirmed in **Silverline Forum Vs. Rajiv Trust AIR 1998 SC 1756**, and **Rajesh Vs. Sreenath AIR 1998 SC 1827**.

In **Tanzeem-e-Sufia Vs. Bibi Haliman, AIR SC 3083**, the Hon'ble Supreme Court clarified that even if the objector files a separate suit to establish their right, title, or interest in the disputed property, the executing court retains the jurisdiction to address and decide objections under Order XXI Rule 97.

Order XXI Rule 98 – Orders After Adjudication

1. Once the issues under Rule 101 have been decided, the court may:
 - (a) Allow the application and order possession to be handed over to the applicant; or
 - (b) Pass any other appropriate order based on the case's circumstances.
2. If it is established that the obstruction or resistance was unjustified and caused by the judgment-debtor, someone representing them, or a transferee during the pendency of the suit or execution, the court shall direct that the applicant be granted possession. If resistance continues, the court may further order detention of the obstructing party for up to 30 days.

Order XXI Rule 99 – Dispossession by Decree-Holder or Purchaser

1. If a person (other than the judgment-debtor) is unlawfully dispossessed by a decree-holder or auction purchaser, they can file an application with the court alleging such dispossession.
2. The court shall then adjudicate the matter as per the applicable provisions.

This rule is meant to protect individuals who are not judgment-debtors but are still dispossessed by a decree-holder or purchaser. Such persons may establish their independent right or claim over the property.

Order XXI Rule 100 – Order on Application Complaining of Dispossession

Once the court resolves the issues listed under Rule 101, it shall either:

- (a) Grant the application and order that the applicant be restored to possession; or
- (b) Issue such orders as deemed appropriate under the circumstances.

Order XXI Rule 101 – Questions to Be Determined

All disputes, including those concerning ownership, possession, or legal interest in the property, that arise between parties or their representatives during proceedings under Rule 97 or 99 must be decided by the executing court itself. These matters are to be decided within execution proceedings and not by a separate civil suit. The court is deemed to have full jurisdiction for these purposes regardless of contrary provisions in other laws.

In **Vol Builders Pvt. Ltd. & Anr. Vs. Janab Salim Saheb & Anr., 2009 (1) JCR 318 (Jhr)**, it was held that when an objector files a suit for declaration based on an agreement to sell, and another party files a suit for injunction on the same subject, the executing court should not begin a separate inquiry, knowing that the matter is sub judice.

In **Sushilkumar Sureka Vs. Santosh Kumar Singh, 2009(3) JCR 740 (Jhr)**, the court observed that repeated objections under Rules 98 to 101 that were rejected even up to the High Court, followed by a new suit from the objector's father, amounted to a gross misuse of legal process. The order was set aside with a nominal cost of ₹2,500.

Order XXI Rule 102 – Rule Inapplicable to Transferee Pendente Lite

Rules 98 and 100 do not apply to persons who acquired the property from the judgment-debtor after the original suit was instituted. Such transfers are hit by the doctrine of *lis pendens*, which is recognized in **Section 52 of the Transfer of Property Act, 1882**. "Transfer" here also includes transfers by operation of law.

In **Usha Sinha Vs. Dina Ram & Others (2007) 7 SCC 144**, the Hon'ble Supreme Court explained the rationale behind this rule. It stressed that granting protection to those who knowingly purchase property during litigation would undermine the rights of decree-holders and obstruct justice.

Order XXI Rule 103 – Orders to Be Treated as Decrees

Any final order passed under Rules 98 or 100 after adjudication is considered equivalent to a decree. Thus, it is appealable just like any decree.

In **Jogindera Kaur @ Jogenderkaur Vs. Kali Prasad @ Kalu Prasad, 2003 (2) JCR (Jhr) 149**, the Hon'ble Court confirmed that adjudications under Rules 97, 98, 99, 100, and 101 are to be treated as decrees, and both first and second appeals are maintainable. However, if the application is dismissed outright without adjudication (at the threshold), such an order is not considered a decree and is therefore not appealable.

Order XXI Rule 104 – Effect of Pending Suits

Orders passed under Rule 101 or 103 are subject to the result of any pre-existing suits concerning the same property, provided those suits were already filed before the start of the execution proceedings.

Execution of Decree with Police Assistance (Order XXI Rule 97 CPC)

In **Rahul S. Shah Vs. Jitendra Kumar Gandhi reported in 2021(2) JLJR (SC) 459**, the Hon'ble Supreme Court issued clear directives:

- Execution proceedings should be concluded within six months from the date of filing; any extension must be justified with written reasons.
- If the court believes police help is essential to enforce the decree, it may direct the local police station to provide assistance.
- If any offence is committed against a public servant during execution, strict legal action must follow.
- Judicial Academies must prepare manuals and conduct regular training for court staff and officers responsible for executing warrants, attachments, sales, and other duties under court orders.

PROBLEMS THAT ARE FREQUENTLY FACED IN THE EXECUTION PROCESS OF RECOVERY OF POSSESSION OF IMMOVABLE PROPERTY

PROBLEM NO. 1:

Resistance Due to Locked Premises During Execution of Possession Warrant

THE ISSUE:

In several cases, when the Bailiff or Court Amin reaches the site to execute a warrant of possession, the property is found locked. This raises a practical dilemma — whether the executing team has the authority to break open the lock or door to deliver possession to the decree-holder, especially in the absence of the judgment-debtor or occupant.

LEGAL POSITION AND SOLUTION:

Yes, the Court has the authority to direct breaking open of the lock or door if necessary to execute the decree of possession.

As per **Order XXI Rule 35(3) of the Code of Civil Procedure**, if the person in possession is bound by the decree but obstructs delivery by locking the premises or being absent, **the Court through its officers is empowered to remove or open any lock or bolt, break open any door, or do any act necessary to put the decree-holder in possession.**

This principle was upheld in the case of:

G. Kethamma v. Allam Keshava Raju, 2008 (2) ALD 179

The Hon'ble Andhra Pradesh High Court ruled that under Rule 35(3), when resistance to possession is due to the property being locked, **the executing officer can legally break open the lock** to give effect to the decree, provided the decree is binding on the person in possession.

PROBLEM NO. 2:

Property in Possession of Tenant of Judgment-Debtor — Can Physical Possession Be Given to Decree-Holder?

THE ISSUE:

During execution of a decree for possession, the executing court may find that the property is in the lawful possession of a **tenant or sub-tenant** of the judgment-debtor. The question arises: Can the Court forcibly evict such occupants and deliver physical possession to the decree-holder?

LEGAL POSITION AND SOLUTION:

When a property is in the occupancy of a **tenant or any other person lawfully entitled to remain in possession**, and such person is **not bound by the decree**, the Court **cannot deliver actual physical possession** by evicting the occupant. Instead, the Court must execute the decree by **delivering symbolic possession**.

As per **Order XXI Rule 36 of the Code of Civil Procedure:**

“Where a decree is for the delivery of any immovable property in the occupancy of a tenant or other person entitled to occupy the same and not bound by the decree to relinquish such occupancy, the Court shall order delivery to be made by affixing a copy of the warrant in some conspicuous place on the property, and proclaiming the substance of the decree by beat of drum or other customary mode.”

This means **symbolic possession** is to be delivered, not actual eviction.

Judicial Precedent:

B. Gangadhar v. B.G. Rajalingam, AIR 1996 SC 780

The Hon'ble Supreme Court held that **where tenants or sub-tenants were not parties to the suit** and are not rank trespassers, they **cannot be forcibly evicted**. The decree-holder is entitled only to **symbolic possession**, and may have to initiate separate legal proceedings against such occupants if actual possession is to be obtained

PROBLEM NO. 3:

Judgment-Debtor Constructs on Property During Suit — Can Such Constructions Be Removed During Execution?

THE ISSUE:

At the stage of executing a decree for possession, it is often found that the **judgment-debtor has raised constructions or built structures** on the suit property **during the pendency of the suit**. The question arises — can the executing court direct demolition of such constructions while delivering possession?

LEGAL POSITION AND SOLUTION:

Yes, the executing court has the power to **order removal or demolition of unauthorized construction** made by the judgment-debtor **pendente lite** (during the pendency of the suit), to give **effective and meaningful possession** to the decree-holder.

As per **Order XXI Rule 35(3) of the Code of Civil Procedure**, the executing court is empowered to: "*Remove or open any lock or bolt or break open any door or do any other act necessary for putting the decree-holder in possession.*" This includes **removal of constructions or obstructions** created to frustrate the execution process.

Judicial Precedent:

B. Gangadhar v. B.G. Rajalingam, AIR 1996 SC 780

The Hon'ble Supreme Court held that:

Rule 35(3) of Order 21 itself manifests that when a decree for possession of immovable property was granted and delivery of possession was directed to be done, the Court executing the decree is entitled to pass such incidental, ancillary or necessary orders for effective enforcement of the decree for possession. That power also includes the power to remove any obstruction or super-structure made *pendente lite*. The exercise of incidental, ancillary or inherent power is consequential to deliver possession of the property in execution of the decree.

PROBLEM NO. 4:

Movable Property of Judgment-Debtor Found in the Premises at the Time of Delivering Possession — What Should Be Done?

THE ISSUE:

During the execution of a decree for possession, it often happens that the premises contains **movable property belonging to the judgment-debtor**. If the judgment-debtor is **absent** or **refuses to remove** the movables, the executing officer is faced with a dilemma — should the possession be denied to the decree-holder, or should the movables be removed forcibly?

LEGAL POSITION AND SOLUTION:

The presence of movable property **does not bar** the execution of possession decree. The proper course is to **inventory the movable items**, hand them over to the decree-holder in **safe custody**, and seek further orders from the Court regarding their disposal.

This principle was affirmed in:

Dr. Annapurna Acharjee v. Sri Pravash Roy

The Hon'ble Court held that **when movable property is found inside the premises** during execution, and the judgment-debtor is not present or refuses to remove them, the executing officer should:

1. Prepare an **inventory of the movable items** in the presence of **independent witnesses**.
2. Leave the movable property in the **custody of the decree-holder**, after taking a **bond for safe custody**.
3. Submit a detailed **report to the Court** along with the inventory.

SUBSEQUENT STEPS BY THE COURT:

1. **Notice** should be issued to the judgment-debtor to take back the movables within a stipulated time.
2. If the notice is not served, a **newspaper publication** and **notice on court premises** may be made.
3. If the judgment-debtor fails to appear or remove the movables:
 1. They may be **auctioned**, with sale proceeds used to cover custody and auction costs.
 2. Any remaining balance is to be **refunded to the judgment-debtor**.
4. If the movables are **perishable**, they should be **immediately auctioned**, and the judgment-debtor should be called upon to collect the proceeds.

"Execution is the fruit & end of the suit and is very life of the law"

-- Justice Vivian Bose

TABLE OF LANDMARK DECISIONS IN EXECUTION JURISPRUDENCE

S. No.	Case Name	Citation	Gist of the Judgment
1	Rahul S. Shah v. Jinendra Kumar Gandhi	(2021) 6 SCC 418	Issued binding directions to streamline execution process and prevent delay tactics; emphasized early asset disclosure and penal consequences for obstruction.
2	Periyammal (Dead thr. LRs.) v. V. Rajamani & Anr.	SLP(C) Nos. 8490–8492/2020	Resistance by strangers not claiming through JD must be decided under Order XXI Rules 101–103 CPC. Court directed enforcement in favor of decree-holder.
3	Shreenath & Anr. v. Rajesh & Ors.	(1998) 4 SCC 543	Obstructionist with independent possession can seek remedy under Rule 97; separate suit is not required.
4	Sundar Dass v. Ram Prakash	(1977) 2 SCC 662	Executing court cannot go behind or examine correctness of the decree. It must be enforced as it stands.
5	Bhoj Raj Garg v. Goyal Education & Welfare Society & Ors.	SLP (C) No. 19654/2022	Decree-holders should not be denied possession due to technical delays; emphasized strict adherence to execution rules.
6	G. Kethamma v. Allam Keshava Raju	2008 (2) ALD 179	Under Rule 35(3) CPC, if the property is locked, the executing officer may break open the lock to deliver possession if the decree binds the occupant.
7	B. Gangadhar v. B.G. Rajalingam	AIR 1996 SC 780	Tenants or sub-tenants not party to suit and not trespassers cannot be forcibly evicted; decree-holder is entitled only to symbolic possession.
8	Dr. Annapurna Acharjee v. Sri Pravash Roy	C.O. 54 of 2020	If movables are found during execution and JD is absent or refuses to remove them, officer must inventory, take bond from DH, and submit report to the court.
9	Haryana Vidyut Prasaran Nigam Ltd. v. Gulshan Lal	(2009) 13 SCC 354	Executing court cannot issue directions inconsistent with the decree; decree is binding unless set aside.
10	Pratibha Singh v. Shanti Devi	(2003) 2 SCC 330	If decree-holder is dispossessed during pendency of execution, executing court must restore possession without forcing fresh litigation.

"The sword of justice is not paper it must be wielded with resolve and result"

-- Justice V.R. Krishnan Iyer

LIST OF SUCCESSFUL EXECUTION OF WARRANTS AND DISPOSAL

जिला स्थापना गुना पर जनवरी 2025 से जुलाई 2025 तक न्यायालयों द्वारा प्रवर्तन प्रकरणों में जारी कब्जा वारंट का पालन कराया जाकर डिक्रीधारी को सफलता पूर्वक संपत्ति का कब्जा प्रदान किया गया।

स.क्र.	न्यायालय का नाम	प्रकरण क्रमांक	उन्मान	निर्वाह कराने वाले कर्मचारी का नाम	निष्पादन दिनांक
1	श्री डालचन्द, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, गुना	EXA 17/2024	जमील उल्ला खान विरुद्ध शशिबाई राठौर	सुरेश मांझी, सेल अमीन	03-01-2025
2	श्री राजकुमार तोरनिया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, गुना	EXA 07/2024	परमसुख विरुद्ध लक्ष्मीनारायण	वीरेन्द्र सिंह परिहार, नायब नाजिर	11-01-2025
3	सुश्री आयुषी मित्तल, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, गुना	EXA 11/2021	दौलतराम लोधा विरुद्ध श्रीमती ममता रघुवंशी	बालकृष्ण शर्मा, जिला नाजिर	10-03-2025
4	कृ. मधुलिका मुले, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, गुना	EXA 37/2018	अख्तर विरुद्ध शहजाद खां	सुरेश मांझी, सेलामीन	06-03-2025
5	सुश्री आयुषी मित्तल, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, गुना	EXA 06/2020	लक्ष्मण सिंह, बृजभान यादव एवं शिशुपाल यादव	बालकृष्ण शर्मा, जिला नाजिर	17-03-2025
6	श्री चेतन बजाड़, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, गुना	EXA 31/2017	इमरतलाल धाकड़ विरुद्ध अर्जुन सिंह किरार	बालकृष्ण शर्मा, जिला नाजिर	21-03-2025
7	श्री राजकुमार तोरनिया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, गुना	EXA 46/2018	हनुमंत सिंह विरुद्ध शंकरसिंह	बालकृष्ण शर्मा, जिला नाजिर	22-03-2025
8	श्री चेतन बजाड़, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, गुना	EXA 12/2019	नन्नूबाई विरुद्ध बन्नो किन्नर	बालकृष्ण शर्मा, जिला नाजिर	25-03-2025
9	श्री चेतन बजाड़, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, गुना	EXA 1300035/2016	श्यामलाल विरुद्ध शांतिबाई	बालकृष्ण शर्मा, जिला नाजिर	26-03-2025
10	श्री चेतन बजाड़, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, गुना	EXA 14/2023	कल्लू गडरिया विरुद्ध बुंदेलसिंह	बालकृष्ण शर्मा, जिला नाजिर	27-03-2025

11	सुश्री प्रियम सेन, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड चांचौड़ा	EXA 02/2023	लक्ष्मण सिंह विरुद्ध पार्वतीबाई	अनिल सेन, नायब नाजिर	28-03-2025
12	श्रीमती श्रुति चौहान, पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, गुना	EXA 1600032/2015	बलराम यादव विरुद्ध अमरसिंह	बालकृष्ण शर्मा, जिला नाजिर	03-04-2025
13	सुश्री मधुलिका मुले, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, गुना	EXA 700013/2016	पवन कुमार विरुद्ध सुरेशचंद	बालकृष्ण शर्मा, जिला नाजिर	09-04-2025
14	श्रीमती ऋतुश्री गुप्ता, पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, गुना	EXA 235/2025	कल्लू कुशवाह विरुद्ध प्रेमनारायण	बालकृष्ण शर्मा, जिला नाजिर	11-04-2025
15	श्री चेतन बजाड़, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, गुना	EXA 08/2023	राधेश्याम अग्रवाल विरुद्ध श्रीराम ढीमर	सुरेश मांझी, सेलामीन	30-04-2025
16	श्री राजकुमार तोरनिया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, गुना	EXA 26/2025	श्रीमती विमला दुबे विरुद्ध श्रीमती रजनी दुबे	बालकृष्ण शर्मा, जिला नाजिर	05-05-2025
17	श्रीमती श्रुति चौहान, पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, गुना	EXA 20/2021	मोहन सिंह यादव विरुद्ध रविन्द्र सिंह	बालकृष्ण शर्मा, जिला नाजिर	08-05-2025
18	श्रीमती श्रुति चौहान, पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, गुना	EXA 20/2021	मोहन सिंह यादव विरुद्ध रविन्द्र सिंह	बालकृष्ण शर्मा, जिला नाजिर	08-05-2025
19	श्री सुरेश बारगिया, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, गुना	EXA 38/2024	महेश तिवारी विरुद्ध गोविंद अग्रवाल	बालकृष्ण शर्मा, जिला नाजिर	09-05-2025
20	श्री आशीष शर्मा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, राघौगढ़, जिला गुना	EXA 01/2023	राजेन्द्र श्रीवास्तव विरुद्ध शब्बीन खान	अर्जुन जावा, सेल अमीन	15-05-2025
21	कु. मधुलिका मुले, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, गुना	EXA 05/2021	चंदादेवी विरुद्ध नथन सिंह	बालकृष्ण शर्मा, जिला नाजिर	23-05-2025
22	श्री डालचंद, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, गुना	EXA 01/2020	कैलाश शर्मा विरुद्ध प्रो. मेसर्स श्यामसुंदर	बालकृष्ण शर्मा, जिला नाजिर	09-06-2025

23	सुश्री मधुलिका मुले, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, गुना	EXA 17/2025	ओमप्रकाश बंसल विरुद्ध संजीव जैन आदि	बालकृष्ण शर्मा, जिला नाजिर	11-06-2025
24	श्री यश दुबे, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, गुना	EXA 29/2022	महेशचंद झा विरुद्ध रमेशचंद जैन	बालकृष्ण शर्मा, जिला नाजिर	11-06-2025
25	कु. मधुलिका मुले, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, गुना	EXA 10/2019	मानसिंह लोधा विरुद्ध रामभरोसा	बालकृष्ण शर्मा, जिला नाजिर	16-06-2025
26	श्री चेतन बजाड़, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, गुना	EXA 24/2025	भगवती सोनी विरुद्ध आजम अली	बालकृष्ण शर्मा, जिला नाजिर	17-06-2025
27	श्री मनीष भट्ट, जिला न्यायाधीश चांचौड़ा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, चांचौड़ा, जिला गुना	EXA 14/2010	पंकज चौरसिया विरुद्ध रामगोपाल आदि	अनिल सेन, सेल अमीन	20-06-2025
28	सुश्री प्रियम सेन, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड चांचौड़ा	EXA 01/2022	सागोबाई विरुद्ध फूलसिंह	अनिल सेन, नायब नाजिर	20-06-2025
29	सुश्री आयुषी मित्तल, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, गुना	EXA 01/2023	माधुरी जैन विरुद्ध गोपाल अग्रवाल	बालकृष्ण शर्मा, जिला नाजिर	23-06-2025
30	सुश्री आयुषी मित्तल, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, गुना	EXA 01/2023	माधुरी जैन विरुद्ध गोपाल अग्रवाल	बालकृष्ण शर्मा, जिला नाजिर	23-06-2025
31	श्री यश दुबे, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, गुना	EXA 34/2023	जयकुमार जैन विरुद्ध चैनसिंह किरार	बालकृष्ण शर्मा, जिला नाजिर	15-07-2025
32	सुश्री आयुषी मित्तल, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, गुना	EXA 30/2019	सुनील जग्गी विरुद्ध ओमप्रकाश जग्गी	बालकृष्ण शर्मा, जिला नाजिर	17-07-2025
33	सुश्री मधुलिका मुले, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, गुना	EXA 28/2025	परमजीत सिंह विरुद्ध जगदीश कुमार	बालकृष्ण शर्मा, जिला नाजिर	25-07-2025
34	श्री आशीष शर्मा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, राघौगढ़, जिला गुना	EXA 05/2020	तौफान सिंह एवं अन्य विरुद्ध दयाचन्द एवं अन्य	नायब नाजिर प्रदीप शर्मा	26-07-2025

जिला स्थापना गुना पर जनवरी 2025 से जुलाई 2025 तक न्यायालयों द्वारा प्रवर्तन प्रकरणों में जारी कुर्की वारंट का पालन कराया जाकर डिक्रोधारी को सफलता पूर्वक भुगतान योग्य राशि प्रदाय कराई गई।

स. क्र.	न्यायालय का नाम	प्रकरण क्रमांक	उन्मान	निर्वाह कराने वाले कर्मचारी का नाम	निष्पादन दिनांक
1	श्री अमिताभ मिश्र, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला गुना, म0प्र0	EXMJC 74/2022	राजेश्वरी ओझा विरुद्ध शलाउद्दीन	नरेन्द्र सुमन, आदेशिका वाहक	13.01.2025
2	श्री अमिताभ मिश्र, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला गुना, म0प्र0	EXMJC 46/2019	श्रीमती रानी शर्मा विरुद्ध दशरथ पाल	रणवीर रघुवंशी, आदेशिका वाहक	15.01.2025
3	श्री ओमप्रकाश रघुवंशी, पंचम जिला न्यायाधीश जिला गुना, म0प्र0	EXAB 3/2023	श्रीराम ट्रांसपोर्ट फायनेंस कंपनी विरुद्ध सोनू खान	बालकृष्ण शर्मा, जिला नाजिर	11.04.2025
4	श्री ओमप्रकाश रघुवंशी, पंचम जिला न्यायाधीश जिला गुना, म0प्र0	EXAB 6/2024	फाइव स्टार बिजनेस फायनेंस लि. विरुद्ध श्रीमती सपनाबाई धाकड	सुरेश मांझी, सेल अमीन	26.04.2025
5	श्री ओमप्रकाश रघुवंशी, पंचम जिला न्यायाधीश जिला गुना, म0प्र0	EXAB 2/2023	श्रीराम ट्रांसपोर्ट फायनेंस कंपनी विरुद्ध महेन्द्र रघुवंशी	बालकृष्ण शर्मा, जिला नाजिर	07.05.2025
6	श्री ओमप्रकाश रघुवंशी, पंचम जिला न्यायाधीश जिला गुना, म0प्र0	EXAB 2/2023	श्रीराम ट्रांसपोर्ट फायनेंस कंपनी विरुद्ध शाहबाज खान	बालकृष्ण शर्मा, जिला नाजिर	07.05.2025
7	श्री राघवेन्द्र भारद्वाज, चतुर्थ जिला न्यायाधीश, जिला गुना, म0प्र0	EXB 38/2023	श्रीराम ट्रांसपोर्ट फायनेंस कंपनी विरुद्ध मुरारीलाल किरार	संजीव झा, आदेशिका वाहक	08.07.2025
8	श्री ओमप्रकाश रघुवंशी, पंचम जिला न्यायाधीश जिला गुना, म0प्र0	EXB 4/2023	श्रीराम ट्रांसपोर्ट फायनेंस कंपनी विरुद्ध वीरेन्द्र बारेला	रणवीर रघुवंशी, आदेशिका वाहक	17.07.2025
9	श्री ओमप्रकाश रघुवंशी, पंचम जिला न्यायाधीश जिला गुना, म0प्र0	EXB 4/2023	श्रीराम ट्रांसपोर्ट फायनेंस कंपनी विरुद्ध मंगा पटेलिया	रणवीर रघुवंशी, आदेशिका वाहक	17.07.2025
10	श्री डालचंद, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, जिला गुना, म0प्र0	EXA 31/2025	महावीर सिंह राजपूत विरुद्ध कनकश्री मोटर्स	अजीत उप्पल, आदेशिक वाहक	18.07.2025
11	श्री डालचंद, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, जिला गुना, म0प्र0	EXA 31/2025	महावीर सिंह राजपूत विरुद्ध कनकश्री मोटर्स	अजीत उप्पल, आदेशिक वाहक	18.07.2025
12	श्री विधान माहेश्वरी, तृतीय जिला न्यायाधीश, जिला शिवपुरी, म0प्र0 (अन्य स्थापना से प्राप्त)	EXMJC 17/2023	बसंती जाटव विरुद्ध यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस	मुकेश रजक, आदेशिक वाहक	04.03.2025

जिला स्थापना गुना पर जनवरी 2025 से जुलाई 2025 तक न्यायालयों द्वारा प्रवर्तन प्रकरणों में जारी गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन कराया गया।

स.क्र.	न्यायालय का नाम	प्रकरण क्रमांक	उन्मान	निर्वाह कराने वाले कर्मचारी का नाम	निष्पादन दिनांक
1	श्री अमिताभ मिश्र, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला गुना, म.प्र.	EXMJC 45/2018	रामसिंह भिलाला विरुद्ध शिवराज सिंह	मुकेश रजक, आदेशिका वाहक	05.02.2025
2	श्री सुरेश बारगिया, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, गुना	EXB 2700002/2015	विवेक कुमार जैन विरुद्ध फूलसिंह	नरेन्द्र सुमन, आदेशिका वाहक	17.02.2025
3	श्री राधाकिशन मालवीय, द्वितीय जिला न्यायाधीश, गुना, म.प्र.	EXMJC 400038/2016	श्रीमती रुकमणी बाई विरुद्ध मूलचंद किरार	नरेन्द्र सुमन, आदेशिका वाहक	23.07.2025
4	श्री राधाकिशन मालवीय, द्वितीय जिला न्यायाधीश, गुना, म.प्र.	EXMJC 400038/2016	श्रीमती रुकमणी बाई विरुद्ध मूलचंद किरार	नरेन्द्र सुमन, आदेशिका वाहक	23.07.2025
5	श्री राधाकिशन मालवीय, द्वितीय जिला न्यायाधीश, गुना, म.प्र.	EXMJC 400038/2016	श्रीमती रुकमणी बाई विरुद्ध मूलचंद किरार	नरेन्द्र सुमन, आदेशिका वाहक	23.07.2025

वर्ष 2025 में जनवरी से जुलाई माह तक निराकृत प्रर्वतन

Name of the presiding officers		Disposal
1	Shri Amitabh Mishra, Principal District & Sessions Judge, Guna	29
2	Shri Suresh Kumar Choubey Chairman, District Consumer Disputes Redressal Commission Guna	36
3	Shri Dinesh Prasad Mishra Principal Judge Family Court	8
4	Sushri Shailja Gupta,, Ist Distt. & Addl. Sessions Judge, Guna	27
5	Shri Radhakishan Malviya, IIInd Distt. & Addl. Sessions Judge, Guna	18
6	Smt. Sonali Sharma , III rd Distt. & Addl. Sessions Judge, Guna	4
7	Shri Raghvendra Bhardwaj, IV th Distt. & Addl. Sessions Judge, Guna	26
8	Shri. Omprakash Singh Raghuwanshi Vth Distt. & Addl. Sessions Judge, Guna	21
9	Shri Suresh Kumar Suryawanshi VI District & Addl. Sessions Judge, Guna	11
10	Smt. Prachi Patel Distt. & Addl. Sessions Judge, Raghogarh	11
11	Shri Hemant Kumar Agrawal, Distt. & Addl. Sessions Judge, Chachoda	4
12	Shri Manish Bhatt, AJ to Addl. District & Sessions Judge Chachoda	4
13	Sushri Madhulika Muley, C. J. M., Guna	14

14	Shri Dalchand, II Civil Judge Sr. Division, Guna	12
15	Shri Bude singh Solanki,, Civil Judge Sr. Division, Aron	2
16	Shri Sanjeev Pipladiya IInd Civil Judge Sr. Division, Raghogarh	5
17	Shri Yash Dubey Ith Civil Judge Jr. Division, Guna	5
18	Shri Rajkumar Torniya II Civil Judge, Junior Division	8
19	Shri Suresh Bargiya, III Civil Judge, Junior Division	6
20	Shri Chetan Bajad, IVth Civil Judge Jr. Division, Guna	7
21	Smt. Shruti Chouhan, V Civil Judge, Junior Division	6
22	Shushri Ayushi Mittal I Addl. Civil Judge, Junior Division. Guna	16
23	Shri Ashish Sharma IInd Civil Judge, Junior Division, Raghogarh	3
24	Shri Ravi Tanwar, Ist AJ To Civil Judge, Junior Division,Raghogarh	3
25	Smt. Dimple Kashyap, Ist Civil Judge, Junior Division, Chachoda	3
26	Shushri Priyam Sen IInd Civil Judge, Junior Division, Chachoda	3
	TOTAL	292

JUSTICE IN MOTION: TALES AND PHOTOGRAPHS OF TRIUMPH

निष्पादन अभियान में न्यायदान की सक्रियता के विभिन्न सोपान

— 1 —

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड गुना, (श्री डालचंद) जिला गुना म0प्र0 के न्यायालय में लंबित निष्पादन प्र.क्र.EX A-17/2024 जमीलउल्ला विरुद्ध शशिबाई, जो कि दुकान व गोदाम का कब्जा वापसी एवं शेष किराया राशि प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रकरण में (निष्पादन अभियान अंतर्गत) नजारात अनुभाग के अथक एवं त्वरित प्रयास से महज एक वर्ष के अंदर ही अचल संपत्ति का न केवल कब्जा अपितु शेष किराया राशि के वसूली डिक्री अनुसार डिक्रीधारी के पक्ष में सार्थक रूप से निष्पादित कराया जाकर इस प्रकरण का निराकरण किया गया।

किसी भी डिक्री के निष्पादन में न्यायालय का यह अहम दायित्व होता है कि जिस व्यक्ति के पक्ष में डिक्री पारित की गयी है, उसे उसका लाभ मिल सके, निष्पादन प्रकरण का निष्पादन, उस दायित्व के सफल के निर्वाहन का द्योतक है।



प्रधान जिला न्यायाधीश गुना (श्री अमिताभ मिश्र) जिला गुना म0प्र0 के न्यायालय में गत 6 वर्षों से लंबित EX MJC- 0000046/2019 में निर्णीत ऋणी से 4,11,200/— रुपये की वसूली हेतु, निर्णीत ऋणी की चल संपत्ति ट्रैक्टर को कुर्क करने हेतु कुर्की वारंट जारी किया गया था। उक्त कुर्की वारंट की तामीली में नजारत अनुभाग जिला गुना के अथक प्रयासों एवं त्वरित कार्यवाहियों के फलस्वरूप निर्णीत ऋणी दशरथ पाल की चल सम्पत्ति ट्रैक्टर को कुर्क किया गया, जिसकी नीलामी की कार्यवाही वर्तमान में न्यायालय में प्रक्रियाधीन है।



प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश गुना (सुश्री आयुषी मित्तल) जिला गुना म0प्र0 के न्यायालय में लंबित प्रकरण क्रमांक EXA-11/2021 दौलतराम लोधा विरुद्ध श्रीमती ममता रघुवंशी, जो कि वर्ष 2021 से लंबित था। उक्त निष्पादन प्रकरण कब्जा प्राप्ति की सहायता हेतु संस्थित किया गया था, जिसमें न्यायालय एवं नजारत अनुभाग के कर्मचारीगण जिला नाजिर, नायब नाजिर, सेल अमीन, आदेशिका वाहक श्री मुकेश रजक, श्री नरेन्द्र सुमन, श्री अजीत उप्पल, भृत्य श्री ओमकार तिवारी एवं सहयोगकर्ता टीम राजस्व विभाग, राजस्व निरीक्षक श्री शत्रुघन सिंह रघुवंशी एवं हल्का पटवारी जिला गुना के अथक प्रयासों से त्वरित कार्यवाही करते हुये डिक्री का निष्पादन सुनिश्चित करते हुये अंततः डिक्रीधारी को दिनांक-10.03.2025 को संपूर्ण वादग्रस्त भूमि का रिक्त आधिपत्य प्राप्त हो गया और इस दीर्घकालीन विवाद का पटाक्षेप हो गया है।



प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड गुना (सुश्री मधुलिका मुले) जिला गुना म0प्र0 के न्यायालय में लम्बित प्रवर्तन प्रकरण क्रमांक EXA/37/2018 अख्तर खॉ विरुद्ध शहजाद खॉ, जो कि वर्ष 2018 से लम्बित था, उसमें डिक्रीधारी एवं निर्णीत ऋणी के मध्य राजीनामा हो जाने से मूल प्रकरण का निराकरण किया गया था, यद्यपि राजीनामा होने के बावजूद अख्तर खॉ द्वारा उसके हिस्से का कब्जा देने से मना किया जा रहा था एवं न्यायालय द्वारा प्रेषित सूचना पत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना किया जा रहा था तब न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया कि पक्षकारों को अनिवार्यतः सूचना पत्र जारी किया जावे, और उनके उपस्थित होने अथवा न होने की दशा में अथवा उपस्थित होने पर कब्जा लेने से मना किये जाने की दशा में विधिवत पंचनामा बनाया जाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाये। उक्त प्रकरण में न्यायालय एवं नजारेत अनुभाग के कर्मचारीगण के अथक प्रयास के बावजूद पक्षकारों द्वारा कब्जा लेने से इंकार किये जाने पर प्रकरण की कार्यवाही न्यायालय द्वारा समाप्त की गई।

पुनः डिक्रीधारी अख्तर खॉ द्वारा पुनः दिनांक 12.04.2025 को प्रवर्तन प्रकरण क्रमांक EXA/27/2025 अख्तर खॉ विरुद्ध शहजाद खॉ दर्ज कराया गया तथा न्यायालय द्वारा पक्षकारों को राजीनामा का पालने करने की समझाईश दिये जाने एवं नजारेत अनुभाग के कर्मचारियों द्वारा दिनांक 17.05.2025 को डिक्रीधारी को डिक्री अनुसार अचल संपत्ति का रिक्त आधिपत्य प्रदान कराया गया।

प्रवर्तन प्रकरण क्रमांक—310/2007 x 2013 मफरत खान विरुद्ध सर्वेश अरोरा, उपभोक्ता आयोग में वर्ष 2013 से लंबित था जिसमें पारित किये गये आदेश दिनांक 26.09.2007 के अनुसार सर्वेश अरोरा को वाहन क्रमांक एम.पी.15 जी 0736 को शिवपुरी से लाकर डिक्रीधारी मफरत खान को उसके कब्जे में देना था और डिक्रीधारी सर्वेश अरोरा को 1,58,632/— रुपये की राशि अदा करनी थी। उक्त प्रवर्तन प्रकरण में इस आयोग द्वारा त्वरित कार्यवाही की जाकर डिक्रीधारी को आदेशित वाहन क्रमांक एम.पी.15 जी 0736 का आधिपत्य दिनांक 24.03.2025 को दिलवाया गया और डिक्रीधारी से सर्वेश अरोरा आदेश राशि 1,58,632/— रुपये का भुगतान कराया जाकर उक्त प्रवर्तन प्रकरण को दिनांक 24.03.2025 को पूर्ण संतुष्टि में निराकृत किया गया।

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश गुना (सुश्री आयुषी मित्तल) जिला गुना म0प्र0 के न्यायालय में निष्पादन प्रकरण क्रमांक EXA-06/2020 चतुर सिंह कुशवाह विरुद्ध लक्ष्मण यादव, वर्ष 2020 से लंबित था और कब्जा प्राप्ति की सहायता हेतु संस्थित किया गया था। उक्त निष्पादन प्रकरण में न्यायालय एवं नजारत अनुभाग के कर्मचारीगण जिला नाजिर, नायब नाजिर, सेल अमीन, आदेशिका वाहक श्री मुकेश रजक, श्री नरेन्द्र सुमन, श्री अजीत उप्पल, भृत्य श्री ओमकार तिवारी एवं सहयोगकर्ता टीम राजस्व विभाग, राजस्व निरीक्षक श्री शत्रुघन सिंह रघुवंशी एवं हल्का पटवारी जिला गुना द्वारा अथक प्रयासों से डिक्री का निष्पादन सुनिश्चित करते हुए डिक्रीधारी को वादग्रस्त भूमि का रिक्त आधिपत्य दिलाया गया। डिक्रीधारी के चेहरे पर न्यायदान मिलने की संतुष्टि एवं प्रसन्नता छायाचित्र में परिलक्षित है।



चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, गुना (श्री चेतन बजाड़) जिला गुना म0प्र0 के न्यायालय में प्रवर्तन प्रकरण EXA/31/2017, दिनांक 03.10.2017 से लंबित था, जो कि अचल संपत्ति के कब्जा प्राप्ति की सहायता हेतु संस्थित किया गया था। उक्त निष्पादन प्रकरण में वादग्रस्त भूमि पर फसल खड़ी होने से राजस्व विभाग सीमांकन की कार्यवाही नहीं कर पा रहे थे तथा निर्णीत ऋणी उस पर लगातार फसल बो रहा था, जिस कारण से डिक्रीधारी को भूमि का कब्जा दिलाने में समस्या उत्पन्न हो रही थी परंतु संबंधित न्यायालय एवं नजारत अनुभाग के कर्मचारीगण के अथक प्रयासों से त्वरित कार्यवाही करते हुये, लगभग आठ वर्ष के अंतराल पश्चात् डिक्री का निष्पादन सुनिश्चित करते हुये, वादग्रस्त कृषि भूमि का कब्जा सीमांकन उपरांत अंततः डिक्रीधारी को मौके पर प्रदत्त किया गया।



द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, गुना (श्री राजकुमार तोरनिया) जिला गुना म0प्र0 के न्यायालय में लंबित प्रकरण क्रमांक EX-A 46/2018 में मुकदमेबाजी की लम्बी दास्तां है। डिक्रीधारी द्वारा 31 वर्ष पूर्व भूमि क्रय की गई थी किंतु विक्रेता द्वारा विवाद किये जाने के कारण दुर्भाग्यवश वह कब्जा प्राप्त करने से वंचित रहा तब उसने न्यायालय में वाद दायर किया और न्यायालय द्वारा दिनांक 05.10.2002 को कब्जा प्रदान किये जाने की निर्णय एवं डिक्री पारित की गई किंतु राजस्व विभाग द्वारा नक्शा जीर्ण-शीर्ण होने से, उसे कब्जा दिलाने में असमर्थता दिखाई गई तब न्यायालय द्वारा सक्रियता दिखाई गई, विभिन्न राजस्व स्तरों पर पत्राचार कर राजस्व अधिकारियों को आहूत कर, मूल अभिलेख से राजस्व नक्शे की प्रमाणित प्रति प्राप्त की गयी और प्रकरण में सलग्न विक्रय पत्र, निर्णय एवं डिक्री अनुसार चतुर्सीमाएं निर्धारित करते हुए दिनांक 24.03.2025 को कब्जा वारंट के पालन में नजारत अनुभाग की टीम के सहयोग से कब्जा दिलाया गया। इस प्रकार भूमि क्रय किये जाने के 31 वर्ष पश्चात डिक्रीधारी को न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि का कब्जा दिलवाया गया।

किसी भी किसान के लिए उसका खेत माता के समान होता है, अतः डिक्रीधारी को उसके खेत का कब्जा मिल जाने से उसके मन को परम संतुष्टि मिली और वह नये जोश के साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिये तत्पर हो गया।



चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, (श्री चेतन बजाड) जिला गुना म0प्र0 के न्यायालय में प्रवर्तन प्रकरण EXA/1300035/2016, जो कि दिनांक 14.01.2016 अर्थात् करीब 9 वर्ष से लंबित था। उक्त निष्पादन प्रकरण कृषि भूमि के कब्जा प्राप्ति की सहायता हेतु संस्थित किया गया था, वादग्रस्त कृषि भूमि पर निर्णीत ऋणी द्वारा निर्माण किया जा चुका था तथा अन्य ग्रामीणजन द्वारा भी डिक्री के पश्चात् खुली भूमि होने से अवैध रूप से निर्माण कार्य किये जा रहे थे। निर्णीत ऋणी द्वारा कब्जा देने से इंकार किये जाने के कारण अंततः पुलिस बल एवं नजारत अनुभाग के कर्मचारीगण के अथक प्रयासों से लगभग 9 वर्ष के अंतराल पश्चात् डिक्री का निष्पादन करते हुये उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि का कब्जा डिक्रीधारी को प्रदत्त किया गया।



चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, गुना (श्री चेतन बजाड़) जिला गुना म0प्र0 के न्यायालय में प्रवर्तन प्रकरण EXA/14/2023, दिनांक 12.04.2023 से लंबित था और अचल संपत्ति के कब्जा प्राप्ति की सहायता हेतु संस्थित किया गया था। उक्त निष्पादन प्रकरण में संबंधित न्यायालय एवं नजारत अनुभाग के कर्मचारीगण के अथक प्रयासों से त्वरित कार्यवाही करते हुये लगभग दो वर्ष के अंतराल पश्चात् डिक्री का निष्पादन सुनिश्चित करते हुये कब्जा अंततः डिक्रीधारी को प्रदत्त किया गया। डिक्रीधारी, जो कि एक निर्धन कृषक है, उसे त्वरित न्यायदान मिलने से ग्रामीणजनों की न्याय के प्रति आस्था बढ़ती है।



पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, गुना (श्रीमती श्रुति चौहान) जिला गुना म0प्र0 के न्यायालय में निष्पादन प्रकरण क्रमांक— EXAB/1600032/2015 बलराम यादव विरुद्ध अमर सिंह, वर्ष 2015 से लंबित था और ग्राम गोपालपुरा टकटईया गुना स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 9/3/क रकबा 0.418 हेक्टेयर एवं सर्वे क्रं 21/1 रकबा 0.620 हेक्टेयर पर कब्जा प्राप्ति की सहायता हेतु संस्थित किया गया था। उक्त निष्पादन प्रकरण में कब्जा की कार्यवाही के दौरान अनेक जटिलताये उत्पन्न होने के कारण वादग्रस्त भूमि का कब्जा डिक्रीधारी प्राप्त नहीं कर पा रहा था, फिर माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के सफल मार्गदर्शन में न्यायालय एवं नजारत अनुभाग के कर्मचारीगण जिला नाजिर श्री बालकृष्ण शर्मा, नायब नाजिर श्री वीरेन्द्र सिंह परिहार, सेल अमीन श्री सुरेश मांझी, आदेशिका वाहक श्री मुकेश रजक, श्री नरेन्द्र सुमन, श्री अजीत उप्पल एवं भृत्य श्री ओमकार तिवारी के अथक प्रयासों से प्रभावी कार्यवाही करते हुये अंततः दिनांक 03.04.2025 को डिक्री का निष्पादन किया गया एवं वादग्रस्त भूमि का कब्जा डिक्रीधारी को मौके पर प्रदान किया गया।

न्याय मिलने की संतुष्टि ना केवल व्यक्तिगत स्तर पर होती है, बल्कि यह समाजिक न्याय एवं समानता की भावना को भी मजबूत करती है।



प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, गुना (सुश्री मधुलिका मुले) जिला गुना म0प्र0 के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक— EXA/0700013/2006 पवन कुमार शर्मा विरुद्ध सुरेशचंद्र शर्मा, वर्ष 2006 से लंबित था। उक्त निष्पादन प्रकरण ग्राम पगारा जिला गुना में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 441/1/मिन-1 रकबा 0.465 हेक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 440/2-क मिन-2 रकबा 0.418 हेक्टेयर पर कब्जा प्राप्ति की सहायता हेतु संस्थित किया गया था, उक्त भूमि के कब्जा की कार्यवाही में अनेक विधिक जटिलताये उत्पन्न होने के कारण वादग्रस्त भूमि का कब्जा डिक्रीधारी को मिल नहीं पा रहा था, किंतु न्यायालय द्वारा प्रकरण में की गई त्वरित एवं सतत् कार्यवाही तथा माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के मार्गदर्शन में, न्यायालय एवं नजारत अनुभाग के कर्मचारीगण जिला नाजिर श्री बालकृष्ण शर्मा, नायब नाजिर श्री वीरेन्द्र सिंह परिहार, सेल अमीन श्री सुरेश मांझी, आदेशिका वाहक श्री मुकेश रजक, श्री नरेन्द्र सुमन, श्री अजीत उप्पल एवं भृत्य श्री ओमकार तिवारी के अथक प्रयासों से सक्रियता पूर्वक निष्पादन कार्यवाही करते हुये अंततः दिनांक 09.04.2025 को डिक्री का निष्पादन किया गया एवं वादग्रस्त भूमि का कब्जा डिक्रीधारी को प्रदान किया गया। इस लंबी मुकदमेबाजी का पटाक्षेप होने से न्यायपालिका का पुनीत दायित्व भी पूर्ण हुआ है।



—: 13 :—

पंचम जिला न्यायाधीश गुना (श्री ओमप्रकाश सिंह रघुवंशी) जिला गुना म0प्र0 के न्यायालय में लंबित EXAB/00003/2023 में निर्णीत ऋणी से 1,75,671/— रुपये की वसूली हेतु निर्णीत ऋणी के विरुद्ध चल एवं अचल संपत्ति कुर्क करने हेतु नियमानुसार कुर्की वारंट जारी किया गया था। उक्त कुर्की वारंट की तामीली में नजारत अनुभाग जिला गुना के सार्थक प्रयासों एवं त्वरित कार्यवाहियों के अंततः निर्णीत ऋणी सोनू खॉन की चल एवं अचल संपत्ति कुर्क की गई। निर्णीत ऋणी द्वारा उक्त कुर्की के पश्चात, उपरोक्त संपूर्ण बकाया धनराशि डिक्रीधारी को प्रदान की गई एवं उक्त प्रकरण को संपूर्ण संतुष्टि में समाप्त किया गया।

जब किसी पक्षकार को निष्पादन प्रकरण में न्याय मिलता है तो उसे अन्याय के खिलाफ लड़ने की शक्ति मिलती है और उसे यह महसूस होता है कि उसके अधिकारों का सम्मान किया गया है।

—: 14 :—

पंचम जिला न्यायाधीश गुना (श्री ओमप्रकाश सिंह रघुवंशी) जिला गुना म0प्र0 के न्यायालय में लंबित EXAB/02/2023 में निर्णीत ऋणी से 1,24,700/— रुपये की धनराशि की वसूली हेतु निर्णीत ऋणी की चल एवं अचल संपत्ति को कुर्क करने हेतु कुर्की वारंट जारी किया गया था। उक्त कुर्की वारंट की तामीली में नजारत अनुभाग जिला गुना के अथक प्रयासों एवं त्वरित कार्यवाहियों के योगदान के फलस्वरूप निर्णीत ऋणी शाहबाज खान की चल एवं अचल संपत्ति कुर्क की गई। निर्णीत ऋणी द्वारा उक्त कुर्की के पश्चात उपरोक्त संपूर्ण धनराशि डिक्रीधारी को प्रदान की गई एवं उक्त प्रकरण को संपूर्ण संतुष्टि में समाप्त किया गया।

—: 15 :—

पंचम जिला न्यायाधीश गुना (श्री ओमप्रकाश सिंह रघुवंशी) जिला गुना म0प्र0 के न्यायालय में प्रस्तुत EX AB/06/2024 में निर्णीत ऋणी से 2,25,908/— रुपये की वसूली हेतु न्यायालय द्वारा निर्णीत ऋणी की चल एवं अचल संपत्ति को कुर्क करने हेतु कुर्की वारंट जारी किया गया था। उक्त कुर्की वारंट की तामीली में, नजारत अनुभाग जिला गुना के सद्प्रयासों एवं त्वरित कार्यवाहियों के फलस्वरूप, निर्णीत ऋणी शाहबाज खान की चल एवं अचल संपत्ति कुर्क की गई। निर्णीत ऋणी द्वारा उक्त कुर्की के पश्चात, उपरोक्त संपूर्ण राशि डिक्रीधारी को प्रदान की गई एवं उक्त प्रकरण को संबंधित न्यायालय द्वारा संपूर्ण संतुष्टि में समाप्त किया गया।

पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, गुना (श्रीमती ऋतुश्री गुप्ता) जिला गुना म0प्र0 के न्यायालय में निष्पादन प्रकरण क्रमांक— EX A/00034/2019 कल्लू शाह विरुद्ध इंद्र सेन विगत कई वर्षों से लंबित था। डिक्रीधारी ने उक्त निष्पादन प्रकरण ग्राम करोंद जिला गुना में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 674 रकवा 2.351 हेक्टेयर के कब्जा प्राप्ति की सहायता हेतु संस्थित किया था। उक्त भूमि के कब्जा की निष्पादन कार्यवाही में अनेक विधिक जटिलता एवं विलंब करने की कुचेष्टा के कारण वादग्रस्त भूमि का कब्जा डिक्रीधारी प्राप्त नहीं कर पा रहा था, किंतु न्यायालय द्वारा प्रकरण में त्वरित एवं सतत् कार्यवाही की गयी तथा माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के मार्गदर्शन में न्यायालय एवं नजारत अनुभाग के कर्मचारीगण के अथक प्रयासों से कर्मठतापूर्वक कार्यवाही करते हुये अंततः दिनांक 11.04.2025 को डिक्री का निष्पादन किया गया तथा उक्त वादग्रस्त भूमि का कब्जा डिक्रीधारी को प्रदान किया गया। अपनी भूमि का कब्जा लेने के दौरान डिक्रीधारी कल्लू शाह के परिजन भी मौके पर उपस्थित हुये थे।



चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गुना (श्री चेतन बजाड़) जिला गुना म0प्र0 के न्यायालय में निष्पादन प्रकरण क्रमांक— EX A/08/2023 राधेश्याम अग्रवाल विरुद्ध श्रीराम ढीमर लगभग 2 वर्ष से न्यायालय में लंबित था। डिक्रीधारी ने उक्त निष्पादन प्रकरण में हाट रोड़ श्याम डेयरी के पास स्थित विवादित दुकान के कब्जा प्राप्ति की सहायता हेतु संस्थित किया था। उक्त दुकान के कब्जा की निष्पादन कार्यवाही हेतु कब्जा वारंट जारी किया गया और न्यायालय द्वारा की जा रही त्वरित कार्यवाही तथा नजारात अनुभाग के कर्मचारीगण जिला नाजिर श्री बालकृष्ण शर्मा, नायब नाजिर श्री वीरेन्द्र सिंह परिहार, सेल अमीन श्री सुरेश मांझी, आदेशिका वाहक श्री मुकेश रजक, श्री रणवीर सिंह रघुवंशी, श्री नरेन्द्र सुमन, श्री अजीत उप्पल एवं भृत्य श्री ओमकार तिवारी के सक्रियता पूर्वक की गई कार्यवाही से दिनांक 30.04.2025 को डिक्री का निष्पादन पूर्ण हुआ और डिक्रीधारी को विवादित दुकान का कब्जा दिलाया जाकर कब्जा प्राप्ति की रसीद प्राप्त की गई। उक्त निष्पादन प्रकरण का दो वर्ष के भीतर ही पूर्ण संतुष्टि में निराकरण हुआ और डिक्रीधारी को न्याय प्राप्त हुआ।



द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, गुना (श्री राजकुमार तोरनिया) जिला गुना म0प्र0 के न्यायालय में प्रस्तुत निष्पादन प्रकरण क्रमांक EX-A 26/2025 में न्यायालय द्वारा त्वरित प्रभावी कार्यवाही करते हुये प्रथम पेशी पर ही कब्जा वारंट जारी किया गया और फिर नजारत अनुभाग के सार्थक एवं सफल प्रयासों के फलस्वरूप कब्जा वारंट की तामीली कराते हुए दिनांक 06.05.2025 को डिक्रीधारी को भूमि का कब्जा दिलाया गया। इस प्रकार मात्र एक माह की अल्प समयावधि में डिक्रीधारी को भूमि का कब्जा दिलाया गया। निष्पादन प्रकरणों के ऐसे प्रभावी क्रियान्वयन में संबंधित न्यायालय, पक्षकारों के विद्यमान अधिवक्तागण एवं न्यायालय की मशीनरी अर्थात् नजारत अनुविभाग सभी का योगदान अत्यंत सराहनीय है।



पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, गुना (श्रीमती श्रुति चौहान) जिला गुना म0प्र0 के न्यायालय में प्रस्तुत निष्पादन प्रकरण क्रमांक— EXA/20/2021 मोहन सिंह राजपूत आदि विरुद्ध रविन्द्र उर्फ टिल्लू रघुवंशी आदि, वर्ष 2021 से लंबित था। उक्त निष्पादन प्रकरण कुशमोदा प.ह.नं. 77, सर्वे क्रमांक 35 व 36 में स्थित भू-खंड 50 X 40 = 2000 वर्गफीट पर कब्जा प्राप्ति की सहायता हेतु संस्थित किया गया था, उक्त प्रकरण में समय-समय पर आने वाले अंतरिम आवेदनों तथा कब्जा की कार्यवाही में अनेक विधिक बाधाएं उत्पन्न होने के कारण वादग्रस्त भूमि का कब्जा डिक्रीधारी को प्राप्त नहीं हो पा रहा था, किंतु संबंधित न्यायालय द्वारा प्रकरण में शीघ्रता से अंतरिम आवेदनों के निराकरण किया गया तथा न्यायालय एवं नजारात अनुभाग के कर्मचारीगण जिला नाजिर श्री बालकृष्ण शर्मा, नायब नाजिर श्री वीरेन्द्र सिंह परिहार, सेल अमीन श्री सुरेश मांझी, आदेशिका वाहक श्री रणवीर रघुवंशी, श्री नरेन्द्र सुमन, श्री अजीत उप्पल एवं भृत्य श्री ओमकार तिवारी के अथक प्रयासों से त्वरित कार्यवाही की गई। अंततः दिनांक 08.05.2025 को डिक्री का निष्पादन पूर्ण करते हुये वादग्रस्त प्लॉट का कब्जा डिक्रीधारी को प्रदान किया गया।



तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, गुना (श्री सुरेश बारगिया) जिला गुना म0प्र0 के न्यायालय में लंबित निष्पादन प्रकरण EXA/38/2024 स्व. महेशकुमार तिवारी द्वारा वारिसान विरुद्ध गोविंद प्रकाश अग्रवाल आदि दिनांक 25.11.2024 वर्ष से लंबित था। उक्त निष्पादन प्रकरण विवादित दुकान के कब्जा प्राप्ति की सहायता हेतु संस्थित किया गया था, जिसमें निष्पादन न्यायालय एवं नजारत अनुभाग के कर्मचारीगण के अथक प्रयासों से त्वरित कार्यवाही की गयी और लगभग 6 माह के अंतराल के भीतर डिक्री का निष्पादन सुनिश्चित करते हुये वादग्रस्त दुकान का कब्जा अंततः डिक्रीधारी को मौके पर सफलतापूर्वक प्रदत्त किया गया।



माननीय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, गुना (श्री डालचंद) जिला गुना म0प्र0 के न्यायालय में निष्पादन प्रकरण EXA/01/20210 कैलाश नारायण शर्मा बनाम प्रोपरायटर मेसर्स श्यामसुंदर रमेशचंद द्वारा गजानंद जी शर्मा पुत्र स्व0 गुजरमल जी शर्मा, वर्ष 2010 से लंबित था। उक्त लंबित निष्पादन प्रकरण में सदर बाजार गुना में स्थित दुकान, जिसकी पश्चिम में चौड़ाई लगभग साढ़े तीन फीट और पूर्व में चौड़ाई लगभग सात फीट एवं गहराई लगभग 18 फीट के कब्जा प्राप्ति की सहायता हेतु संस्थित किया गया था, जिसमें निष्पादन न्यायालय एवं नजारत अनुभाग के कर्मचारीगण के अथक प्रयासों से त्वरित कार्यवाही की गयी वादग्रस्त दुकान का कब्जा अंततः डिक्रीधारी को दिनांक 09.06.2025 को प्रदत्त किया गया।



प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, गुना (सुश्री मधुलिका मुले) जिला गुना म0प्र0 के न्यायालय में निष्पादन प्रकरण क्रमांक— EXA/05/2021 श्रीमती चंदादेवी विरूद्ध नथन सिंह आदि वर्ष 2021 से लंबित था। उक्त निष्पादन प्रकरण चौरसिया कॉलोनी, ग्राम छावनी नगर पालिका गुना स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 97 मिन-1 में से भू-खंड क्रमांक 77 पूर्व-पश्चिम 13 फीट लंबा एवं उत्तर-दक्षिण 40 फीट लंबा कुल 550 वर्गफीट का कब्जा प्राप्ति की सहायता हेतु संस्थित किया गया था, जिसमें न्यायालय एवं नजारत अनुभाग के कर्मचारीगण जिला नाजिर श्री बालकृष्ण शर्मा, नायब नाजिर श्री वीरेन्द्र सिंह परिहार, सेल अमीन श्री सुरेश मांझी, आदेशिका वाहक श्री रणवीर रघुवंशी, श्री नरेन्द्र सुमन, श्री अजीत उप्पल के अथक प्रयासों से त्वरित कार्यवाही करते हुये 04 वर्ष के अंदर ही डिक्री का निष्पादन सुनिश्चित करते हुये वादग्रस्त मकान का कब्जा अंततः डिक्रीधारी को दिनांक 23.05.2025 को प्रदान किया गया।



प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, गुना (सुश्री मधुलिका मुले) जिला गुना म0प्र0 के न्यायालय में निष्पादन प्रकरण क्रमांक EXA/10/2019 मान सिंह विरुद्ध रामभरोसा व अन्य, वर्ष 2019 से लम्बित था, जिसमें नजारत द्वारा निरंतर प्रयास किये जाने के उपरांत भी कब्जा दिलाये जाने की डिक्री का निष्पादन नहीं हो पा रहा था, तब न्यायालय द्वारा उक्त संबंध में तहसीलदार एवं क्षेत्र से संबंधित पटवारी को कब्जे दिलाये जाने की कार्यवाही के समय नजारत के कर्मचारियों के साथ उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया गया। तदुपरांत डिक्रीधारी मान सिंह को वादग्रस्त भू-भाग का कब्जा प्रदान कराया जाकर दिनांक 17.06.2025 को निष्पादन की कार्यवाही पूर्ण संतुष्टि में समाप्त हुई।



प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, गुना (श्री यश दुबे) जिला गुना म0प्र0 के न्यायालय में निष्पादन प्रकरण EX MJC/29/2022 महेशचंदर झा मृत वारिसान नूतन झा विरुद्ध रमेशचंद्र जैन लगभग 3 वर्ष से लंबित था। उक्त निष्पादन प्रकरण सदर बाजार गुना में स्थित दुकान के कब्जा प्राप्ति की सहायता हेतु संस्थित किया गया था, जिसमें न्यायालय एवं नजारत अनुभाग के कर्मचारीगण के अथक प्रयासों से त्वरित कार्यवाही करते हुये वादग्रस्त दुकान का कब्जा अंततः डिक्रीधारी को दिनांक 11.06.2025 को प्रदत्त किया गया और निष्पादन कार्यवाही पूर्ण संतुष्टि में समाप्त की गयी।



प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, गुना (सुश्री मधुलिका मुले) जिला गुना म0प्र0 के न्यायालय में निष्पादन प्रकरण EXA/17/2025 ओमप्रकाश बंसल मृत वारिसान गीतादेवी आदि विरुद्ध संजीव जैन आदि के नाम से लंबित था। उक्त निष्पादन प्रकरण सदर बाजार गुना में स्थित दुकान के कब्जा प्राप्ति की सहायता हेतु संस्थित किया गया था, जिसमें न्यायालय एवं नजारत अनुभाग के कर्मचारीगण के अथक प्रयासों से त्वरित कार्यवाही करते हुये वादग्रस्त दुकान का कब्जा अंततः डिक्रीधारी को दिनांक 11.06.2025 को प्रदत्त किया गया। उक्त प्रकरण का शीघ्र निराकरण पूर्ण संतुष्टि में हुआ।



चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, गुना (श्री चेतन बजाड़) जिला गुना म0प्र0 के न्यायालय में निष्पादन प्रकरण EXA/24/2025 भगवती सोनी विरुद्ध आजम अली आदि दिनांक 12.04.2025 को कब्जा प्राप्ति की सहायता हेतु संस्थित किया गया था। उक्त निष्पादन प्रकरण में निर्णीत ऋणी द्वारा वादग्रस्त भूखंड पर निर्माण कर लिया गया था किंतु न्यायालय द्वारा उक्त निर्माण तुडवाकर तथा न्यायालय एवं नजारत अनुभाग के कर्मचारीगण के अथक प्रयासों से त्वरित कार्यवाही करते हुये मात्र दो माह के अंतराल के भीतर ही दिनांक 18.06.2025 को डिक्री का निष्पादन सुनिश्चित करते हुये वादग्रस्त भूमि का कब्जा अंततः डिक्रीधारी को प्रदत्त किया गया। इस तरह त्वरित न्याय मिलने से लोगों का विधि व्यवस्था में विश्वास बढ़ता है, जो कि सामाजिक स्थिरता के लिए परम आवश्यक है।



प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश गुना (सुश्री आयुषी मित्तल) जिला गुना म0प्र0 में निष्पादन प्रकरण EXA/01/2023 माधुरी जैन पत्नी नरेन्द्र जैन द्वारा मुख्तयारआम नरेन्द्र जैन विरुद्ध गोपाल आदि लंबित था। उक्त निष्पादन प्रकरण गुना जिला गुना की सर्वे क्रमांक 838 मिन प0ह0नं0-75, वार्ड क्रमांक 24 में ब्लॉक क्रमांक 24 पूर्व से पश्चिम तक 30 फीट तथा उत्तर से दक्षिण तक 50 फीट कुल क्षेत्रफल 1500 वर्गफीट भूमि के कब्जा प्राप्ति की सहायता हेतु संस्थित किया गया था, जिसमें न्यायालय एवं नजारत अनुभाग के कर्मचारीगण के अथक प्रयासों से त्वरित कार्यवाही करते हुये वादग्रस्त मकान का कब्जा अंततः डिक्रीधारी को दिनांक 17.06.2025 को प्रदत्त किया गया। इस तरह न्यायालय से मानवाधिकारों का संरक्षण होता है और यह विश्वास स्थापित होता है कि लोकतंत्र में सभी के साथ सम्मान एवं गरिमा का व्यवहार किया जाए तथा विधि का पालन किया जाए।



द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड राघौगढ़ (श्री आशीष शर्मा) जिला गुना म0प्र0 की न्यायालय में निष्पादन प्रकरण ई.एक्स ए 01/2023 राजेन्द्र श्रीवास्तव आदि विरुद्ध शब्बीर खान आदि वर्ष 2023 लंबित था। उक्त निष्पादन प्रकरण निर्णीतऋणी शब्बीर खां द्वारा मंदिर श्री गिरधारीजी महाराज स्थित लालापुरा राघौगढ़ की पश्चिम दिशा की दीवार से लगकर स्थित शासकीय गली में डिक्रीधारी के सुखाचार को बाधित करते हुए किये गये अतिक्रमण हटाकर उक्त शासकीय गली रिक्त करने की सहायता हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिसमें न्यायालय द्वारा नजारत अनुभाग के कर्मचारीगण नायब नाजिर श्री कैलाश कुशवाह, सेल अमीन श्री अर्जुन जावा एवं आदेशिका वाहक श्री मोहन मोरे द्वारा पुलिस बल के सहयोग एवं अथक प्रयासों से राघौगढ़ के संवेदनशील क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द को कायम रखते हुए लगभग दो वर्ष के अंतर्गत ही डिक्री का निष्पादन सुनिश्चित करते हुए विधिवत शासकीय गली में किया गया निर्माण को ध्वस्त करते हुए डिक्रीधारी को डिक्री अनुसार सुखाचार मुहैया करवाते हुए डिक्री का निष्पादन दिनांक 15.04.2025 को सुनिश्चित किया गया।



द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड चाचौडा (सुश्री प्रियम सेन) जिला गुना म0प्र0 में निष्पादन प्रकरण EX A/01/2022 सागोबाई वि. फूलसिंह वर्ष 2022 से लंबित था। उक्त निष्पादन प्रकरण में मूल व्यवहार वाद क्रमांक आर.सी.एस.ए. 22/2019 में पारित डिक्री अनुसार डिक्रीधारी सागोबाई पत्नी हरगोविन्द्र कंजर, उम्र 68 वर्ष, निवासी ग्राम भानपुराबाबा, तहसील चाचौडा, जिला गुना म.प्र. के पक्ष में न्यायालय की ओर से नायब नाजिर श्री अनिल सेन, के माध्यम से ग्राम तेलीगांव, तहसील चाचौडा, जिला गुना म.प्र. में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 172/2/क/2 रकबा 1.043 हे. व भूमि सर्वे क्रमांक 179/1 रकबा 0.505 हे., के संबंध में विक्रय पत्र का निष्पादन कर पंजीयन कराया जाकर डिक्रीधारी को वादग्रस्त भूमि का आधिपत्य प्रदान किया गया। उक्त प्रकरण पूर्ण संतुष्टि में दिनांक 20.06.2025 को समाप्त किया गया।

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड चाचौडा (सुश्री प्रियम सेन) जिला गुना म0प्र0 में निष्पादन प्रकरण EX A/02/2023 लक्ष्मण सिंह विरुद्ध पार्वतीबाई वर्ष 2023 से लंबित था। उक्त निष्पादन प्रकरण में मूल व्यवहार वाद क्रमांक आर.सी.एस.ए. 01/2023 में पारित डिक्री अनुसार डिक्रीधारी लक्ष्मण सिंह पुत्र भारत सिंह गूजर, उम्र 45 वर्ष, व्यवसाय कृषि, निवासी वार्ड क्रमांक 15 कुंभराज, तहसील कुंभराज, जिला गुना म.प्र. के पक्ष में न्यायालय की ओर से नायब नाजिर श्री अनिल सेन, के माध्यम से कस्बा कुंभराज, तहसील कुंभराज, जिला गुना म.प्र. में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 794 रकबा 1.254 हे. व भूमि सर्वे क्रमांक 795 रकबा 0.188 हे., कुल किता 02 रकबा 1.442 हे. के 1/2 यानी रकबा 0.722 हे. के संबंध में विक्रय पत्र का निष्पादन कर पंजीयन कराया जाकर डिक्रीधारी को वादग्रस्त भूमि का आधिपत्य प्रदान किया गया। उक्त प्रकरण पूर्ण संतुष्टि में दिनांक 28.03.2025 को समाप्त किया गया।

प्रधान जिला न्यायाधीश श्री अमिताभ मिश्र के न्यायालय के प्रवर्तन प्रकरण क्रमांक ई-एक्स एमजेसी/6/2025 पदमा बाई विरुद्ध कुन्दन सिंह आदि में निर्णीतऋणीगण के विरुद्ध जारी कुर्की वारंट निर्वाह हेतु नजारत अनुभाग गुना में प्राप्त होने पर और निर्वाह कराए जाने पर बीमा कंपनी की ओर से चैक क्रमांक 011667 द्वारा राशि 327367 जमा की गई है। उक्त राशि का आवेदकगण को भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

निष्पादन प्रकरणों के त्वरित निराकरण एवं न्याय मिलने से समाज में न्यायपालिका के प्रति यह विश्वास बढ़ता है कि न्याय व्यवस्था निष्पक्ष है और यह लोगों को न्याय के लिए लड़ने हेतु न्यायालय के समक्ष आने में प्रोत्साहित करती है।



प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, गुना (सुश्री मधुलिका मुले) जिला गुना म.प्र. के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक— EXA/28/2025 परमजीत सिंह विरुद्ध जगदीश कुमार दिनांक 16.04.2025 को वादग्रस्त दुकान स्थित हाट रोड गुना के रिक्त आधिपत्य दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा कब्जा वारंट दिनांक 21.07.2025 को जारी किया गया और दिनांक 25.07.2025 को ही डिक्रीधारी को उसकी वादग्रस्त दुकान का आधिपत्य प्राप्त हो गया। उक्त निष्पादन प्रकरण में न्यायालय द्वारा की गई त्वरित कार्यवाही तथा माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के मार्गदर्शन में न्यायालय एवं नजारत अनुभाग के कर्मचारीगण जिला नाजिर श्री बालकृष्ण शर्मा, नायब नाजिर श्री वीरेन्द्र सिंह परिहार, श्री भुभम झा, आदेशिका वाहक श्री मुकेश रजक, श्री नरेन्द्र सुमन, एवं भृत्य श्री ओमकार तिवारी के तत्काल प्रयासों से प्रथम बार कब्जा वारंट जारी किये जाने पर ही वादग्रस्त दुकान का कब्जा डिक्रीधारी को प्राप्त हो गया। उक्त निष्पादन प्रकरण प्रस्तुति दिनांक से लगभग 03 माह के भीतर ही निराकृत हो गया।

मदयून को जिला नाजिर द्वारा वारंट पढाकर सुनाया व समझाया गया



विवादित दुकान

न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, राघौगढ़, जिला गुना, म.प्र. की न्यायालय में निष्पादन प्रकरण ई.एक्स.ए. 05/2020 तौफान सिंह एवं अन्य विरुद्ध दयाचन्द एवं अन्य, फरवरी 2020 से लंबित था। उक्त निष्पादन प्रकरण डिक्रीधारी पक्ष द्वारा ग्राम विजयपुर तहसील राघौगढ़, जिला गुना, म.प्र. में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 472/3 रकबा 1.254 हेक्टेयर में से रकबा 0.418 हेक्टेयर का रिक्त आधिपत्य प्राप्त करने की सहायता हेतु प्रस्तुत किया गया था। निर्णीतऋणी पक्ष द्वारा उक्त विवादित भूमि पर पक्के मकान का निर्माण कर लिया गया था, जिसका रिक्त आधिपत्य निर्णीतऋणी पक्ष द्वारा डिक्रीधारी को प्रदान नहीं किया जा रहा था, कोरोनाकाल में लॉकडाउन के दौरान लगभग 1 वर्ष उक्त प्रकरण की कार्यवाही स्थगित रही, तत्पश्चात् न्यायालय द्वारा विभिन्न अवसरो पर कब्जा वारंट जारी किये गये, परन्तु कब्जा कार्यवाही के दौरान लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति निर्मित होने एवं अनैक जटिलताएं उत्पन्न होने के कारण लंबे समय तक डिक्रीधारी उक्त भूमि पर कब्जा प्राप्त करने से वंचित रहा, किन्तु न्यायालय द्वारा की गई त्वरित एवं सतत् कार्यवाही तथा माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय के कुशल मार्गदर्शन, पुलिस अधीक्षक गुना तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के सहयोग तथा न्यायालय के नजारत अनुभाग के कर्मचारीगण नायब नाजिर श्री प्रदीप शर्मा, सेल अमीन श्री अर्जुन जावा, आदेशिका वाहक श्री मोहन मौरे के अथक प्रयासों से सक्रियता पूर्वक लोक शांति कायम रखते हुए, उक्त भूमि पर निर्णीतऋणी पक्ष द्वारा किये गये अवैध निर्माण को विधिवत् ध्वस्त करते हुए अन्ततः दिनांक 26.07.2025 को डिक्रीधारी पक्ष को डिक्री अनुसार उनके पक्ष में निर्णीत भूमि का रिक्त आधिपत्य पूर्ण संतुष्टि में प्रदान किया गया।

न्यायालय के आदेश पर अवैध कब्जा हटाया गया

वास्तविक भू-स्वामी को सौंपी जमीन



न्यायालय के आदेश पर कब्जा हटकर भू-स्वामी को सौंपा गया।

विजयपुर तहसील में स्थित सर्वे नंबर 472/3, रकबा 1.254 हेक्टेयर भूमि जो तौफान सिंह के नाम पर दर्ज है, उस पर से न्यायालय के आदेश के पालन में अवैध कब्जा हटाया गया। इस भूमि के एक हिस्से, रकबा 0.418 हेक्टेयर पर दयाचंद पुत्र बुद्धलाल, अर्जुन पुत्र दयाचंद तथा रामस्वरूप पुत्र दयाचंद (जाती अहिरवार, निवासी ग्राम बेलकत्र) द्वारा लंबे समय से कब्जा कर अवैध रूप से मकान बनाकर निवास किया रहा था। इस मामले में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, राघौगढ़ के माननीय न्यायालय द्वारा अवैध निर्माण को हटाने और वास्तविक भू-स्वामी को कब्जा दिलाने का आदेश पारित किया गया था। आदेश के अनुपालन में नायब तहसीलदार, हल्का पटवारी गिरधवल, नजीर, तथा पुलिस बल की उपस्थिति में मौके पर कार्रवाई कर कब्जा हटाया गया और परीकरी को वैधानिक कब्जा प्राप्त किया गया।



THE ROAD FORWARD

The success of *Mission Kriya Siddhi* has ignited a spark — a renewed belief that decree execution, often seen as the weakest link in the chain of justice, can become its strongest pillar. Yet, this mission is not an end; it is a beginning. The road forward lies in **transforming this movement into a mindset** — where every executing court treats each decree not as a file number, but as a promise of justice waiting to be fulfilled.

- **From Campaign to Culture:** What began as a focused drive must now evolve into a permanent judicial culture. Regular review mechanisms, timelines, and prioritization of execution matters must become embedded in daily functioning.
- 1. **Empowering the Execution Court:** Judicial officers must be supported with robust administrative tools, coordination from police and revenue machinery, and full institutional backing to assert the dignity of the court's orders.
- 2. **Encouraging Innovation and Initiative:** Courts should be encouraged to devise local strategies — from surprise inspections to early morning executions — that suit their unique challenges, and these should be documented and shared for collective learning.
- 3. **Stakeholder Sensitization:** Continue sensitizing decree-holders, police authorities, and revenue officials about the importance of supporting the execution process proactively.
- 4. **Replicating the Model:** The model, processes, and learnings of *Kriya Siddhi* must be shared with other districts and zones, with the goal of making decree execution a priority across the state.

**"A decree is not a decoration to be framed and hung on a wall.
It is a solemn command of the court which must be obeyed and enforced"
-- Justice Markandey Katju**

CONCLUSION

The journey of *Kriya Siddhi* has reaffirmed a fundamental truth — **that the effectiveness of the execution process is not a function of physical resources but of judicial will, strategic resolve, and coordinated effort**. The success of this mission stands as a testament to what can be achieved when every limb of the justice system acts with purpose, clarity, and compassion for the rights of decree-holders.

While challenges remain, the achievements under this initiative have laid a solid foundation for future reforms. With sustained energy and collective resolve, the ideals of *Kriya Siddhi* — **“Achievement through Action”** — will continue to guide our courts toward



**"The credibility of the entire Judicial System is at stake
if a decree passed by a competent court is not effectively excuted"**
-- Justice Dalveer Bhandari





We the Judges of Civil Court Guna

*"The woods are lovely,
dark and deep.
But I have promise to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep....."*

- Robert Frost